A Daily News Magazine
भोपाल
गुरुवार, 09 जुलाई, 2026
भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित
वर्ष 23, अंक 307, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

डोनाल्ड ट्रंप का इतिहास या इतिहास पर कब्जा?

त्रिभुवन

द न्यूयॉर्क टाइम्स की रविवार की एक विस्तृत पड़ताल ने अमेरिकी लोकतंत्र के सामने एक असहज प्रश्न रख दिया है। प्रश्न केवल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नहीं, उस सीमा का है, जहां सत्ता इतिहास लिखना शुरू कर देती है।

अमेरिका के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के जाने माने इतिहासविदों लैरी बुकानन, कैरेन योरिश, डग मिल्स, जॉन हुआंग और राज साहा की रिपोर्ट के अनुसार, ह्वाइट हाउस के वेस्ट विंग को राष्ट्रपति निवास से जोड़ने वाले एक व्यस्त गलियारे में ट्रंप ने सोने के अक्षरों वाली पट्टिकाओं के माध्यम से अमेरिका के 47 राष्ट्रपतियों का एक नया आधिकारिक आख्यान गढ़ा है। पहली नज़र में यह एक संग्रहालयीय, सजावटी या शैक्षिक प्रयोग लग सकता है; लेकिन रिपोर्ट बताती है कि यह राष्ट्रपति इतिहास का निष्पक्ष परिचय नहीं, स्मृति पर सत्ता का निजी दावा है।

न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन पट्टिकाओं की तस्वीरें लीं और डेमोक्रेटिक तथा रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों पर अध्ययन और लेखन कर चुके आठ प्रतिष्ठित इतिहासकारों से उनका मूल्यांकन कराया। निष्कर्ष असहज करने वाले हैं। इतिहासकारों को इनमें तथ्यगत गलतियां, खंडित प्रस्तुतियां, चयनित मौन, अपमानजनक टिप्पणियां, ट्रंप के बारे में अतिश्योक्तियां, लिजलिजा आत्म-प्रचार और शैलीगत विचित्रताएं मिलीं।

प्रिंसटन विश्वविद्यालय के इतिहासकार सीन विलेन्ट्ज़ ने इसे केवल 'खराब इतिहास' नहीं, 'इतिहास-विरोधी' कहा। यह अंतर मामूली नहीं है। खराब इतिहास गलती कर सकता है; इतिहास-विरोधी लेखन इतिहास की मूल आत्मा- स्रोत, संदर्भ, संतुलन, जटिलता और असुविधाजनक सत्य को ही अस्वीकार कर देता है। यह पूरी प्रदर्शनी लगभग 5,400 शब्दों में फैली है। ह्वाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने स्वीकार किया कि इनमें से कई पट्टिकाएं राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वयं लिखी हैं। लेकिन जब टाइम्स ने पूछा कि इन विवरणों के लिए किन स्रोतों का इस्तेमाल किया गया तो ह्वाइट हाउस ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। इतिहास-लेखन में स्रोत छुपा लेना अपने-आप में एक राजनीतिक संकेत है। यह कहता है: इसे इतिहास की तरह नहीं, घोषणा की तरह पढ़िए। इतिहासविदों की टिप्पणियों की आपत्तियों का सार यह है कि ट्रंप ने ह्वाइट हाउस की दीवारों पर इतिहास नहीं लिखा; उन्होंने इतिहास की शक्ल में अपना राजनीतिक आत्ममुग्धता का चित्र टांग दिया है।

इतिहास को हर सत्ता अपने ढंग से पढ़ती है। फर्क इतना है कि लोकतंत्र में इतिहास सत्ता की परीक्षा लेता है; अधिनायकवादी प्रवृत्ति में सत्ता इतिहास को अपनी परीक्षा देने पर मजबूर करती है। ट्रंप की यह राष्ट्रपति-दीर्घा इसी दूसरी प्रवृत्ति का उदाहरण लगती है। इसमें अतीत स्वतंत्र नहीं है। वह वर्तमान राष्ट्रपति की वैधता का सहायक पात्र है। पूर्व राष्ट्रपति अपने समय के जटिल मनुष्य नहीं रह जाते; वे ट्रंप की राजनीतिक पटकथा के चरित्र बन जाते हैं। यहां समस्या किसी एक गलत तारीख या किसी एक अतिरंजित विशेषण की नहीं है। समस्या यह है कि पूरी प्रस्तुति का नैतिक ढांचा ही तिरछा, बांका और टेढ़ामेढ़ा है। हाल के राष्ट्रपतियों, विशेषकर जो बाइडेन और बराक ओबामा, के संदर्भ में भाषा अधिक तीखी, कटु और दलगत हो जाती है। पहले के राष्ट्रपतियों के विवरण अपेक्षाकृत शांत दिखते हैं, लेकिन वे भी ट्रंप की प्राथमिकताओं के अनुरूप इतिहास को पुनर्गठित करते हैं। यह इतिहास किसी निष्पक्ष संग्रहालय की दीवार पर कम और चुनावी रैली के बैनर पर अधिक स्वाभाविक लगेगा।

दूसरी ओर जिन राष्ट्रपतियों से ट्रंप अपनी वैचारिक वंशावली बनाना चाहते हैं, उनके प्रति भाषा अधिक उदार हो जाती है।

पट्टिकाओं में टैरिफ का 18 बार उल्लेख भी आकस्मिक नहीं है। ट्रंप की आर्थिक राष्ट्रवाद की भाषा में टैरिफ लगभग एक पवित्र राजनीतिक उपकरण बन चुके हैं। इसलिए अमेरिकी इतिहास में भी उन्हें बार-बार ऐसे पेश किया गया है, जैसे वे राष्ट्रीय शक्ति और आर्थिक स्वायत्तता की शाश्वत कसौटी हों। इसी तरह मुनरो सिद्धांत की बार-बार प्रशंसा की गई है- वह सिद्धांत जिसे ट्रंप पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी प्रभुत्व और हस्तक्षेप की अपनी समझ के साथ जोड़ते रहे हैं। इतिहास में जिन प्रसंगों से वर्तमान नीति को वैधता मिलती है, वे रोशन कर दिए जाते हैं। जिनसे असुविधा होती है, वे छाया में रख दिए जाते हैं।

इतिहास में चूक भी भाषा होती है। जो नहीं कहा गया, वह भी उतना ही बोलता है जितना कहा गया। यदि भ्रष्टाचार, सत्ता-दुरुपयोग और संस्थागत संकटों को धुंधला रखा जाए, जबकि शुल्कों, राष्ट्रवाद और मजबूत नेतृत्व की कथाएं बार-बार दोहराई जाएं तो यह संपादन नहीं, विचारधारात्मक कतरब्योंत है।

सबसे विचित्र और शायद सबसे ईमानदार संकेत यह है कि ट्रंप स्वयं छह पूर्व राष्ट्रपतियों के परिचयों में उपस्थित हैं।

ह्वाइट हाउस कोई निजी क्लब नहीं है। वह अमेरिकी राष्ट्र-राज्य की प्रतीक-स्थली है। वहां लगी दीवारों, चित्रों और शब्दों का अर्थ किसी होटल लॉबी की सजावट जैसा नहीं होता। वे नागरिकों को बताते हैं कि राष्ट्र स्वयं को कैसे याद करता है। यही कारण है कि इस प्रदर्शनी की समस्या केवल अकादमिक नहीं है। यह सार्वजनिक स्मृति की समस्या है। जब कोई राष्ट्रपति राष्ट्र की स्मृति को अपनी राजनीतिक आत्मकथा में बदल देता है तो सार्वजनिक संस्थान निजी स्मारक बनने लगता है।

हर आधुनिक नेता जानता है कि इतिहास केवल अतीत नहीं है। वह वैधता की मुद्रा है। जो अतीत को नियंत्रित करता है, वह वर्तमान पर नैतिक दावा पेश करता है। इसलिए सत्ता केवल कानून नहीं बदलती; वह पाठ्यपुस्तकें बदलती है, स्मारक बनाती और गिराती है, संग्रहालयों की भाषा बदलती है, राष्ट्रीय नायकों की सूची संशोधित करती है और खलनायकों की पहचान तय करती है। ट्रंप की यह प्रदर्शनी उसी वैश्विक प्रवृत्ति का अमेरिकी संस्करण है।

हर जगह प्रश्न एक ही है: अतीत किसका है? लोकतंत्र का उत्तर स्पष्ट होना चाहिए: अतीत नागरिकों का है, शासक का नहीं।

इतिहास का काम नेता को महान सिद्ध करना नहीं, नागरिक को जटिलता से परिचित कराना है। वह बताता है कि अच्छे निर्णय भी बुरे परिणाम दे सकते हैं; महान नेता भी दोषपूर्ण हो सकते हैं; राष्ट्र गौरव और अपराध दोनों से बनते हैं; और किसी भी राजनीतिक परंपरा को बिना आलोचना के पवित्र बना देना नागरिक बुद्धि के विरुद्ध है। जब इतिहास सत्ता का घोषणापत्र बन जाता है, तो नागरिक विवेक धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है।

ट्रंप की सोने के अक्षरों वाली राष्ट्रपति-दीर्घा अंततः एक अनजाने में की गई आत्मस्वीकृति है। यह दर्पण है, लेकिन राष्ट्र का नहीं- शासक का। लोकतंत्रों को ऐसे दर्पणों से सावधान रहना चाहिए। सुनहरे अक्षर इतिहास को अधिक सत्य नहीं बनाते; कई बार वे झूठ को अधिक चमकीला बना देते हैं। इसलिए जब हम देखते हैं कि भारत में बार-बार प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कमतर आंकने की कोशिश होती है तो साफ़ दिखता है कि मौजूदा दौर में एक विकृत प्रतिध्वनि सब जगह गूंज रही है।

(द वायर हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सुप्रभात

घड़ी खोने से समय नहीं खोता
जिन दरवाज़ों पर दस्तक नहीं होती
वे भी कभी–न–कभी खुलते हैं
मन का भी ऐसा ही है
यहाँ खुलते हैं नित नये अर्थ

अंधेरे का नाम प्रतीक्षा भी हो सकता है
उजास का अहंकार भी
कभी–कभी फूल भी चुभ जाते हैं
नींद भी कर देती है क्लांत
वेदना से निर्मित हो सकता
है हँसी का आभूषण

स्पर्श का अर्थ छूना हो ज़रूरी कहाँ
स्वाद और सुवास से
विरक्ति हो सकती है
नैराश्य का विपरीत उम्मीद नहीं सर्वदा
किसी के लिए नैराश्य का प्रतिलोम
घोर–निराशा होता है
तृष्णा और तृप्ति सौतेली
बहनें हो सकती हैं

प्रेम हमें मार देता है अंतत: ।

– श्रुति कुशवाहा

पुणे-दिल्ली में इमारत ढहीं

कई लोग दबे, रेस्क्यू जारी

● खंडाला में लैंडस्लाइड; सूरत में बाढ़, करोड़ों का नुकसान, खाने-पीने की भी दिक्कत ● नासिक में पुल बहा, जोधपुर बाजार में नदी जैसी धार बही

जयपुर/पटना/अहमदाबाद/मुंबई/भोपाल(एजेंसी)। महाराष्ट्र के पुणे में बुधवार को भारी बारिश से कचरे का पहाड़ 3 मंजिला इमारत पर गिर गया। इससे इमारत ढह गई। 16 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मीडियासूत्रों के अनुसार बताया कि पुणे के पिंपरी-चिंचवाड़ में कचरे का पहाड़ जैसा ढेर था, यह वहां मौजूद कचरा प्रबंधन की बिल्डिंग पर गिर पड़ा। वहीं रोहिणी सेक्टर-16 स्थित जी-4 पॉकेट में सोमवार को एक निर्माणाधीन इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे के समय भवन में कई मजदूर काम कर रहे थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है।

देश के कई राज्यों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। जम्मू-कश्मीर के डोडा में बाढ़ के साथ बड़े-बड़े पत्थरों का सैलाब आ गया। कई गाड़ियां, घर और दुकानें मलबे में दब गईं। महाराष्ट्र के नासिक, मुंबई और पुणे में भी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। पुणे के खड़कवासला डैम से 27,303 क्यूसेक पानी मुथा नदी में छोड़ा गया है। नदी के किनारे बसे गांवों में हाई अलर्ट है।नासिक में त्रयंबकेश्वर के दो गांवों को जोड़ने वाला पुल बह गया।

● नासिक में गोदीवरी खतरे के निशान के पार

● पुल-सड़कें बहीं, राजस्थान में सड़कें नदियां बनीं

● एमपी में इमारत गिरी; जम्मू-कश्मीर में पत्थरों का सैलाब

यह मंदिर का परिक्रमा मार्ग भी था। श्रद्धालुओं की एंट्री दो दिन के लिए रोक दी गई है। कई अन्य शहरों में भी बाढ़ की स्थिति है।

इधर, गुजरात के सूरत में 36 घंटे में 11 से 19 इंच तक बारिश हुई। यहां जुलाई 1941 में दर्ज हुई 18 इंच बारिश का 85 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। शहर में बाढ़ आ गई, शॉपिंग मॉल की एक मंजिल पानी में डूब गई। करंट लगने, पेड़ और बिजली गिरने से 9 लोगों की जान चली गई।

मोहन कैबिनेट में हुए कई बड़े फैसले

नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक को मंजूरी

● प्रदेश में अधोसंरचनात्मक विकास और पुनर्वास कार्यों के लिये दी 2,300 करोड़ रूपये की स्वीकृति ● मुख्यमंत्री स्कूटी योजना को 2031 तक निरंतर रखे जाने के लिए 495 करोड़ रूपये की मंजूरी ● मध्यप्रदेश उपार्जित गेहूँ, चना, ज्वार एवं बाजरा निस्तारण नीति – 2026 को मिली स्वीकृति

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को संपन्न हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में अनेक निर्णय लिए गए है। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में अधोसंरचना विकास और पुनर्वास कार्यों को 2300 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। इसी तरह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्ताव अनुसार राज्य डाटा सेंटर के आधुनिकीकरण, आई.टी एवं डिजास्टर रिकवरी सहित अन्य कार्यों के लिए मंत्रि-परिषद ने 800 करोड़ की मंजूरी दी है। विभाग के ही तीन अन्य प्रस्तावों पर विज्ञान पार्क- एकल नागरिक डाटाबेस परियोजना और बॉयो टेक्नालॉजी पार्क की स्थापना एवं संचालन के लिए वर्ष 2031 तक निरंतरता के लिए 123 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

मंत्रि-परिषद ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक और प्रस्ताव अनुसार ईएसडीएम इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 के संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत स्वामित्व योजना के निष्पादित हस्तांतरण अभिलेखों पर अतिरिक्त स्टांप शुल्क से छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा प्रस्तुत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक: 2026 को भी मंत्रि-परिषद ने मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव अनुसार मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री स्कूटी योजना को वर्ष 2031 तक निरंतर रखे जाने के लिए 495 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। इसी तरह खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा प्रस्तुत मध्यप्रदेश उपार्जित गेहूँ, चना, ज्वार एवं बाजरा निस्तारण नीति : 2026 को भी मंत्रि-परिषद ने स्वीकृति दी है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव अनुसार मध्यप्रदेश के 65 नगरीय निकायों और उनके आस-पास के वन क्षेत्रों में नगरीय वन विकसित करने के लिए नमो हरित नगर योजना को 100 करोड़ की स्वीकृति दी है।

रूंज मध्यम और मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना पर भी निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा केन-बेतवा लिंक परियोजना के समान रूंज मध्यम परियोजना से प्रभावित 730 विस्थापित परिवार के लिए प्रति परिवार अतिरिक्त रू. 7.5 लाख (साढ़े सात लाख) की राशि का विशेष पुनर्वास पैकेज कुल रू. 54 करोड़ 75 लाख की स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। यह राशि रूंज मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए प्रशासकीय स्वीकृति राशि 269 करोड़ 79 लाख रुपए के अतिरिक्त होगी।

पीएम मोदी इंडोनेशिया के सबसे बड़े प्रम्बानन हिंदू मंदिर पहुंचे

● बोले- हमेशा शिव से जुड़ने का सौभाग्य मिला; पीएम ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए

जकार्ता (एजेंसी)। पीएम मोदी बुधवार को इंडोनेशिया के योग्याकार्ता स्थित देश के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बानन पहुंचे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी उनके साथ गए। दोनों ने मंदिर के संरक्षण-जीर्णोद्धार परियोजना का उद्घाटन किया। पीएम ने मंदिर में दर्शन भी किए। उन्होंने मंदिर परिसर में अपने संबोधन में कहा- मुझे किसी न किसी रूप में हमेशा भगवान शिव से जुड़ने का मौका मिला है। सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ धाम और उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाद प्रम्बानन मंदिर के विकास का मौका मिलना मेरा सौभाग्य है। पीएम मोदी के इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के लिए रवाना हो गए हैं। वे 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रहेंगे। उन्हें पांच इंडोनेशियाई फाइटर जेट ने एस्कॉर्ट किया।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी-पुलिस को फर्जी रसीद बुक मिली

● आरोपियों ने पैसे ऐंठने की बात कबूली, गोपाल राव का दावा- ट्रस्ट से नहीं हटाया गया

अयोध्या (एजेंसी)। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के तीन आरोपियों लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडेय को पुलिस ने 40 घंटे की रिमांड पर लिया है। पूछताछ के दौरान पुलिस को आरोपियों से श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की पुरानी फर्जी रसीद बुक मिली है। यह रसीद हूबहू असली की तरह दिखती है। इस पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का लोगो बना है।

सूत्रों के मुताबिक, आरोपियों ने पूछताछ में कबूला है कि वे फर्जी रसीद काटकर चंदा देने वालों से पैसे भी ऐंठ लेते थे। शुरुआत में टिन्नू यादव, लवकुश, करुणेश, अनुकल्प समेत अन्य आरोपी जब कोई मंदिर में दान देने की इच्छा जताता था, तो उसे रसीद के तौर पर यह फर्जी रसीद दे देते थे, ताकि किसी को शक न हो। अब नई

व्यवस्था के तहत रसीद ऑनलाइन मिलती है, इसलिए इन लोगों ने इन रसीदों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था।

गोपाल राव ने ट्रस्ट के प्रेस नोट को खारिज किया, बोले- हटाने की बात गलत

ट्रस्ट से हटाए गए गोपाल राव ने दावा किया है कि वह अभी भी ट्रस्टी हैं। उन्हें हटाया नहीं गया है। हटाने की खबरें गलत संदेश है। जबकि सोमवार को ट्रस्ट की बैठक के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जारी किए गए प्रेस नोट में लिखा गया है कि विशिष्ट आमंत्रित सदस्य की सूची से हटा दिया गया है। गोपाल राव का वास्तविक नाम गोपाल नगरकोटे हैं, इसी नाम से उन्हें ट्रस्ट में विशिष्ट आमंत्रित सदस्य बनाया गया था। पुलिस टीम बुधवार सुबह 7 :36 बजे फैजाबाद जेल पहुंची। तीनों आरोपियों को पुलिस लाइन लेकर गई। तब से उनसे पूछताछ जारी है। एसआईटी रिपोर्ट के अनुसार, तीनों आरोपी सीसीटीवी फुटेज में नोटों को जेब में रखते हुए नजर आए थे।

अमरनाथ : प्राकृतिक शिवलिंग पूरी तरह पिघला

● करीब 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का दर्शन करना बाकी

जम्मू (एजेंसी)। अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग लगभग पूरी तरह पिघल गया है। अभी यात्रा के पांच दिन ही बीते हैं। 57 दिन चलने वाली यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी।

यात्रा के पहले चार दिनों में करीब 86 हजार श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। अधिकारियों के अनुसार, मंगलवार को पांचवें दिन यह संख्या 1 लाख के पार पहुंचने की उम्मीद है। यात्रा के लिए इस साल 4 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। यानी कि अभी 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का दर्शन करना बाकी है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ गुरुवार, 09 जुलाई 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

पदोन्नति निर्णय का अधिकारी-कर्मचारियों ने माना सीएम का आभार

मंत्रालय में ढोल-नगाड़े के साथ किया स्वागत-अभिनंदन

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का मंत्रालयीन अधिकारी- कर्मचारियों ने पदोन्नति संबंधी निर्णय और उस पर त्वरित कार्यवाही के लिए मंत्रालय, वल्लभ भवन में पुष्प-गुच्छ भेंट कर आभार माना।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का अधिकारियों-कर्मचारियों ने ढोल-नगाड़े के साथ स्वागत किया तथा पुष्प भेंट कर उनका अभिवादन भी किया। शासकीय सेवकों ने इस उपलब्धि के लिए उत्साह और उल्लास का प्रकटीकरण करते हुए मिठाई वितरित की। इस अवसर पर विधायक श्री भगवान दास सबनानी, अध्यक्ष कर्मचारी कल्याण समिति श्री रमेश शर्मा, अध्यक्ष मंत्रालय कर्मचारी संघ श्री सुभाष वर्मा, अध्यक्ष अजाक्स श्री घनश्याम भकोरिया, म.प्र. राज्य मंत्रालय शा. अधिकारी/कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री ओ.पी. गौर, सहित बड़ी संख्या में मंत्रालय के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

अधिकार और कर्तव्य दोनों के संतुलन से मजबूत होता है लोकतंत्र : विधानसभा अध्यक्ष

स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद रखें, अच्छे नागरिक बनकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं युवा : श्री तोमर

भोपाल। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और प्रत्येक भारतीय के लिए यह गर्व का विषय है। श्री तोमर ने कहा कि लोकतंत्र केवल संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, भौगोलिक सीमाओं अथवा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और संघर्ष का परिणाम है जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। यह उदगार आज विधानसभा के मानसरोवर सभागार में यंग इंडियंस पार्लियामेंट 2026 के कार्यक्रम के समापन सत्र के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने युवा प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का गंभीर अध्ययन करें, ताकि लोकतंत्र के मूल्यों को समझते हुए उसका सही उपयोग कर सकें। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्त करना जितना महत्वपूर्ण था, उससे कहीं अधिक आवश्यक आज लोकतंत्र को सशक्त, स्थायी एवं आदर्श बनाना है, जिससे भारत विश्व के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों का अनुकरणीय उदाहरण बन सके।

अपने संबोधन में श्री तोमर ने अधिकार और कर्तव्य को लोकतंत्र के दो समान रूप से महत्वपूर्ण स्तंभ बताते हुए कहा कि संविधान नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है, वहीं उनके कर्तव्यों का भी बोध कराता है। अधिकार और कर्तव्य दोनों के संतुलित निर्वहन से ही लोकतंत्र मजबूत होता है, जबकि किसी एक पक्ष की उपेक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर सकती है। श्री तोमर ने कहा कि अधिकारों की मांग करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, किंतु उसके साथ कर्तव्यों के प्रति समर्पण और जिम्मेदारी भी उतनी ही आवश्यक है। समाज, राष्ट्र और संस्थाओं के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए ही व्यक्ति स्वयं की प्रगति के साथ-साथ देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। श्री तोमर ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार या आजीविका प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक जिम्मेदार, संवेदनशील एवं संस्कारित नागरिक का निर्माण भी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। विद्यार्थियों को पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं लोकतांत्रिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना चाहिए। नेतृत्व केवल राजनीति तक सीमित नहीं है।

संक्षिप्त समाचार

बंगाल में बवाल

ममता की रैली में भिड़े टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ता, लगे 'चोर-चोर' के नारे

कोलकाता (एजेंसी)। क्या पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस रैली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसके चलते यह झड़प हुई? क्या कोलकाता में राजनीतिक लड़ाई अब इतनी बढ़ चुकी है कि अदालती आदेश के बावजूद सड़कों पर ऐसे ही तमाशे होते रहेंगे? इस टकराव ने बंगाल की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवालिया निशान लगा दिए हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी नेत्री ममता बनर्जी की रैली के दौरान जमकर हंगामा और बवाल हुआ। बालीगंज फाड़ी से हाजरा मोड़ के बीच निकाले जा रहे इस मार्च में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। न्यूज एजेंसी एएनआई के ताजा फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे दोनों तरफ के लोग एक-दूसरे से बुरी तरह उलझ पड़े। इस हंगामे के बाद पूरे इलाके में भारी तनाव है।

लोको पायलट ने समोसे के लिए रोकी ट्रेन

इंदौर में लोग बोले- अक्सर ऐसा ही होता है; रेल विभाग ने बैठाई जांच

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर-महू के बीच चल रही डेमू ट्रेन से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। इसमें ट्रेन रुकी हुई है जबकि लोको पायलट ट्रेक के किनारे बनी एक दुकान पर खड़ा है। वह दुकान से समोसे खरीदता है, फिर इंजन की तरफ बढ़ता है। लोको पायलट के इंजन में चढ़ने के बाद ट्रेन आगे बढ़ जाती है।

जेडीयू की नई टीम का ऐलान

नीरज कुमार फिर बने मुख्य प्रवक्ता

- 12 उपाध्यक्ष, 38 महासचिव और 74 सचिव नियुक्त

पटना (एजेंसी)। बिहार में संगठन को और मजबूत बनाने की कवायद के तहत जनता दल यूनाइटेड ने बुधवार को अपनी नई प्रदेश टीम का एलान कर दिया। पार्टी नेतृत्व ने इसे संगठन को नई ऊर्जा देने और जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना है। पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के निर्देशन में बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने नए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की। नई टीम में संगठन के विभिन्न स्तरों पर बड़े पैमाने पर जिम्मेदारियों का बंटवारा किया गया है। घोषित सूची के अनुसार, पार्टी ने 12 प्रदेश उपाध्यक्ष, 38 प्रदेश महासचिव और 74 प्रदेश सचिवों की नियुक्ति की है।

मध्यप्रदेश को अब डेढ़ हजार करोड़ रूपए के स्थान पर केवल 217 करोड़ रूपए ही देना होंगे

तीस वर्षों से लंबित सरदार सरोवर परियोजना का सर्वसम्मति से समाधान होना बड़ी उपलब्धि : मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के प्रयासों से विगत 30 वर्षों से सरदार सरोवर परियोजना को लेकर लंबित जटिल मुद्दे का सर्वसम्मति से समाधान हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी, केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह विषय मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच लंबित था। भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा फरवरी 2026 में अभिमत दिया कि पुनर्वास की लागत भागीदार राज्यों के मध्य विभाजित होनी चाहिए। अभिमत के अनुसार मध्यप्रदेश को लगभग डेढ़ हजार करोड़ रुपए का भुगतान करने की स्थिति बन रही थी। नई दिल्ली में हुई बैठक में तय किया गया कि 50 प्रतिशत के स्थान पर 75 प्रतिशत का खर्चा गुजरात द्वारा ही दिया जाए, और इस प्रकार मध्यप्रदेश को अब केवल रूपये 217 करोड़ की राशि देना होगी।

प्रदेश को खेलों में मिली बड़ी सफलता

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश को खेलों में बड़ी सफलता मिली है। जापान में आयोजित अंडर-18 पुरुष और महिला हॉकी एशिया कप-2026 टूर्नामेंट में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक जीते। भारतीय बालक एवं बालिका हॉकी टीम में प्रदेश के कुल 10 खिलाड़ी शामिल रहे। ये खिलाड़ी भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम, सिवनी और बड़वानी जिले के साधारण परिवारों से हैं। राज्य सरकार ने हॉकी स्वर्ण पदक विजेता टीम के खिलाड़ियों को 3 लाख रूपए प्रति खिलाड़ी और कांस्य पदक विजेता टीम के खिलाड़ियों को एक लाख रूपए प्रति खिलाड़ी प्रोत्साहत राशि प्रदान की है।

जल गंगा संवर्धन अभियान में मध्यप्रदेश ने रचा नया इतिहास

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान में मध्यप्रदेश ने नया इतिहास रचा है। प्रदेश में गत तीन वर्षों में 15 हजार 819 करोड़ रूपये लागत के 5 लाख 20 हजार 400 से अधिक कार्य हुए हैं। वर्ष 2024 में 1 हजार 367 करोड़ रूपये लागत से 60 हजार 428 कार्य कराए गए। वर्ष 2025 में 4 हजार करोड़ रूपये लागत के 1 लाख से अधिक कार्य सम्पन्न हुए। वर्ष 2026 में 10 हजार 452 करोड़ रूपये लागत के 3 लाख 60 हजार, कार्य प्रदेश में सम्पन्न हुए। वर्ष 2026 में जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रथम 5 जिले बड़वानी, खण्डवा, नीमच, उज्जैन और खरगोन रहे।

टीकमगढ़ से मिला 10 फीट लंबा जम्बूद्वीप का नक्शा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में में नये अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड का गठन कर लिया गया है। वक्फ बोर्ड का पुर्नगठन करने वाला मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए चलाए जा रही ज्ञान भारतम् योजना में मध्यप्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर आया है। अब तक 34 लाख 45 हजार से अधिक पांडुलिपि पन्नों का पंजीकरण और 12 लाख से अधिक का सत्यापन किया जा चुका है। टीकमगढ़ से 10 फीट लंबा जम्बू द्वीप का नक्शा, पन्ना से रसिक प्रिया, बुरहानपुर से 220 वर्ष पुराना हस्तलिखित श्रीमद्भागवत और दतिया से ऐतिहासिक ताम्रपत्र जैसी अमूल्य धरोहरें प्राप्त हुई हैं।

धार के राजगढ़ में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात

पत्नी की लाश पलंग के बॉक्स में छिपाई, ऊपर रातभर सोता रहा पति

धार (नप्र)। मध्य प्रदेश के धार जिले के राजगढ़ कस्बे से एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। यहां एक कसाई दिल पति ने अपनी 35 साल की पत्नी की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी। हैवानियत की हद तो तब हो गई जब आरोपी ने लाश को अपने ही बेड के स्टोरेज बॉक्स के अंदर ठूंस दिया और रातभर उसी पलंग के ऊपर चैन की नींद सोता रहा।

यह सनसनीखेज मामला राजगढ़ के शंकरपुरा इलाके का है। मृतका की पहचान हिना खराड़ी (35 वर्ष) के रूप में हुई है। वारदात का खुलासा तब हुआ जब पड़ोसियों को हिना मंगलवार सुबह से गायब दिखी और पति कमलेश खराड़ी उसके बारे में पूछने पर गोलमोल जवाब देने लगा। शक होने पर पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

पुलिस पहुंची तो पलंग पर सो रहा था कातिल- कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही जब राजगढ़ थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो आरोपी पति कमलेश उसी पलंग पर आराम से सोया हुआ था। पुलिस ने जब कमरे की तलाशी ली और बेड के बॉक्स को खोला, तो अंदर हिना की लाश देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए।

शुरुआती पूछताछ में आरोपी पति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वह अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था, जिसे लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। सोमवार रात को भी उनके बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद आरोपी ने शराब के नशे में इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया।

सीजफायर खत्म होते ही शेयर मार्केट लहूलुहान

सेंसेक्स 1,900 अंक टूटा

नई दिल्ली (एजेंसी)। घरेलू शेयर बाजार में आज भारी गिरावट आई। बाजार सुबह गिरावट के साथ खुला था लेकिन दोपहर बाद इसमें भारी गिरावट आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। उनका कहना है कि ईरान के साथ सीजफायर खत्म हो गया है। इसके बाद अमेरिका ईरानी 80 ठिकानों पर बमवारी की। इससे कच्चे तेल की कीमत में भारी तेजी आई। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, कमजोर ग्लोबल संकेतों और जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ने से निवेशकों का भरोसा डगमगा गया। इससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 2 प्रतिशत से ज्यादा गिरावट आई।

गुरुग्राम में 10 किमी लंबा जाम

दिल्ली-जयपुर हाइवे धंसा

भारी बारिश के चलते दिल्ली-जयपुर एनएच-48 धंस गया है, जिसके कारण 10 किमी लंबा जाम लगा गया। एक स्कूल बस भी नाले में फंस गई। इधर, गुरुग्राम के कई इलाकों में दो-दो फीट पानी भर गया। पुलिस ने कंपनियों से अगले कुछ दिनों तक कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने की अपील की है।

अरुणाचल में बाढ़-लैंडस्लाइड से 94 हजार लोग प्रभावित- अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश से बाढ़ और लैंडस्लाइड ने 26 जिलों के 94 हजार से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया है। 4 लोगों की मौत हुई है, 21 घायल हैं और 2 महिलाएं लापता हैं। इधर, कर्नाटक के बेलगावी और शिवमोगा में आज स्कूल और आंगनवाड़ी बंद रहेंगे।

महाराष्ट्र-पालघर में बारिश से 10 मौतें, 1261 लोग शिफ्ट- महाराष्ट्र के पालघर में बारिश से 1 जुलाई से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 3 मौतें हुई हैं। प्रशासन ने 389 परिवारों के 1,261 लोगों को सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों में पहुंचाया है।

बिहार कैबिनेट में 22 प्रस्तावों को मंजूरी

सोलर प्लांट से लेकर बेली ब्रिज और केंद्रीय विद्यालय तक पर मुहर

पटना (एजेंसी)। बिहार सरकार ने स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।इनमें सबसे अहम फैसला अगले पांच वर्षों में सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का रहा।यह परियोजना वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। सरकार का लक्ष्य बिजली खर्च घटाने के साथ हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इस पहल को राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

रिटायर्ड एआरटीओ के घर 22 किलो सोना-चांदी मिला

- दीवारों और पैकेटों में छिपाए थे 1.62 करोड़

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में आगरा के तत्कालीन सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) ललित कुमार के लखनऊ स्थित आवास पर दो दिन तक सर्च ऑपरेशन चलाया। तलाशी के दौरान टीम को करीब 1.62 करोड़ रुपए नकद, 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी और करोड़ों रुपये के निवेश व संपत्तियों के दस्तावेज मिले। विजिलेंस ने बरामद संपत्ति की कुल कीमत करीब 35 करोड़ रुपए आंकी है। विजिलेंस की टीम ने 7 और 8 जुलाई को अलीगंज की चंद्रलोक कॉलोनी स्थित सी-143 आवास पर कोर्ट से सर्च वारंट लेकर छापेमारी की।

जंग की आहट तेज, ईरान-अमेरिका में सीजफायर खत्म

अमेरिका ने 80 ठिकानों पर हमले किए, होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमले के बाद एक्शन

तेहरान (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने नॉटो समिट के दौरान कहा कि ईरान के साथ हुआ सीजफायर समझौता अब खत्म हो चुका है और अब वह ईरान से कोई डील नहीं करना चाहते। ट्रम्प ने कहा, हमने पिछली रात ईरान पर जोरदार हमला किया। खतरनाक लोगों को निशाना बनाया। हर बार वे हमला करेंगे, हम जवाब देंगे।

उन्होंने कहा कि अमेरिका का लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना है। ट्रम्प ने नॉटो पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि गठबंधन ने दुनिया के सबसे बड़े आतंक समर्थक देश ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ नहीं दिया।

इससे पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया था कि उसने ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की है। अमेरिका के मुताबिक, यह कार्रवाई होर्मुज में जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई।

ईरान ने होर्मुज में 3 टैंकरों को निशाना बनाया- खामेनेई के अंतिम संस्कार के बीच ईरान ने होर्मुज में 3 टैंकरों को निशाना बनाया, जिसमें एक टैंकर कतर का था। ईरान ने चेतावनी दी कि हमारी तरफ से तय रुट इस्तेमाल नहीं होने पर सुरक्षा की गारंटी नहीं रहेगी।

ईरान बोला- धमकियों के बीच अमेरिका से बातचीत नहीं- ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि धमकियों के माहौल में कोई समझौता नहीं होगा। पहले अमेरिका को अपने पुराने समझौतों का सम्मान करना होगा।

ईरानी तटों को दुश्मन के लिए जहन्नुम बना देंगे... ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार

ईरानी सेना ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरान के वरिष्ठ कमांडर रियर एडमिरल हबीबोल्लाह सय्यारी ने कहा है कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरान की जमीन पर पैर रखते हैं, तो उसे जहन्नुम बना दिया जाएगा। ट्रंप ने बुधवार तड़के अमेरिकी हमले के बाद कहा है कि ईरान के साथ शांति समझौता खत्म हो चुका है।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन प्रगति की समीक्षा की

तकनीक के प्रभावी उपयोग से नागरिकों को बेहतर, त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के अंतर्गत संचालित प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रदेश के अंतिम छोर तक रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुँचाया जाए। उन्होंने कहा कि तकनीक के प्रभावी उपयोग से नागरिकों को बेहतर, त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा आभा आईडी, हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री के माध्यम से डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत किया जाए। बैठक में सीईओ आयुष्मान श्री अरविंद कुमार शाह सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य देश में एकीकृत एवं परस्पर जुड़ा हुआ डिजिटल स्वास्थ्य इको सिस्टम विकसित करना है। इसके माध्यम से नागरिकों को विशिष्ट डिजिटल स्वास्थ्य पहचान आभा आईडी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे वे अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से प्राप्त एवं साझा कर सकें। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निर्देश दिए कि शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य संस्थानों, चिकित्सकों, नर्सों, आयुष चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का पंजीयन तेजी से कराया जाए। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों में डिजिटल सेवाओं के उपयोग को बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता एवं नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से मरीज, चिकित्सक, प्रयोगशाला, फार्मेसी, अस्पताल और बीमा सेवाओं के बीच स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का सुरक्षित एवं निर्बाध आदान-प्रदान संभव होगा। इससे उपचार की निरंतरता, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता तथा प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी।

सीईओ आयुष्मान श्री शाह ने बताया कि प्रदेश में अब तक लगभग 5.86 करोड़ एबीएचए आईडी बनाई जा चुकी हैं। साथ ही लगभग 20 हजार स्वास्थ्य संस्थान हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री में पंजीकृत किए गए हैं तथा लगभग 18 हजार स्वास्थ्य पेशेवर हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री से जुड़ चुके हैं।

स्कैन एंड शेयर से आसान एवं पेपरलेस ओपीडी पंजीयन- समीक्षा में स्कैन एंड शेयर पहल की प्रगति की भी जानकारी दी गई। प्रदेश में वर्तमान में 533 स्वास्थ्य संस्थानों में स्कैन एंड शेयर सुविधा सक्रिय है। इसके माध्यम से अब तक 1 करोड़ 7 लाख 70 हजार 164 से अधिक ओपीडी पंजीयन टोकन जारी किए जा चुके हैं। स्कैन एंड शेयर सुविधा के अंतर्गत मरीज अस्पताल पहुंचकर एबीएचए एप अथवा अन्य एबीडीएम सक्षम एप के माध्यम से अस्पताल का क्यूआर कोड स्कैन करता है। मरीज की सहमति से उसकी मूलभूत जानकारी अस्पताल के डिजिटल सिस्टम में सुरक्षित रूप से साझा होती है और उसे डिजिटल ओपीडी टोकन प्राप्त हो जाता है। इससे मरीजों को लंबी पंजीयन कतारों से राहत मिलती है तथा कागजरहित और त्वरित पंजीयन की सुविधा उपलब्ध होती है।

हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री से स्वास्थ्य संस्थानों का एकीकरण

हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री के अंतर्गत शासकीय एवं निजी अस्पतालों, क्लीनिकों, प्रयोगशालाओं, फार्मेसियों, इमेजिंग सेंटर और वेलनेस सेंटर का पंजीयन किया जा रहा है। प्रत्येक संस्थान को विशिष्ट हेल्थ फैसिलिटी आईडी प्रदान की जाती है। इससे संस्थानों की जानकारी का मानकीकरण होगा तथा उन्हें एबीएचए, स्कैन एंड शेयर एवं नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज जैसी डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जा सकेगा।

हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री से स्वास्थ्य पेशेवरों की डिजिटल पहचान

सीईओ आयुष्मान श्री शाह ने बताया कि हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री के अंतर्गत चिकित्सक, नर्स, दंत चिकित्सक, आयुष चिकित्सक तथा अन्य लाइसेंसधारी स्वास्थ्य पेशेवरों का सत्यापित डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। प्रत्येक पंजीकृत स्वास्थ्य पेशेवर को विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान की जाती है। इससे डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित प्रमाणीकरण, टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार तथा विश्वसनीय डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलती है।

केंद्र सरकार ने दी तमिलनाडु के किसानों के खोपरा और आम खरीदी को मंजूरी

भोपाल/नई दिल्ली। किसानों के हित में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा सकारात्मक फैसला लिया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने तमिलनाडु के खोपरा और तोतापुरी आम उत्पादक किसानों के लिए उनकी उपज की सरकारी खरीद की मंजूरी दी है। इससे किसानों को अपनी फसल का बेहतर दाम मिलेगा और उन्हें घाटे में, मजबूरी में बेचने की स्थिति से राहत मिलेगी।

केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 के दौरान तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव के आधार पर खोपरा की सरकारी खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह द्वारा दी गई इस मंजूरी के तहत राज्य में कुल 87,226 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद की जाएगी, जिसमें 87 हजार मीट्रिक टन मिलिंग खोपरा और 226 मीट्रिक टन बाल खोपरा शामिल हैं। यह पूरी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर, मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। स्वीकृत खोपरा खरीद का कुल एमएसपी मूल्य 1049.16 करोड़ रु. से अधिक रहेगा।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस फैसले से तमिलनाडु के खोपरा उत्पादक किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा

87 हजार 226 मीट्रिक टन खोपरा की खरीदी का लक्ष्य

और उन्हें बाज़ार में गिरती कीमतों के कारण अपनी फसल को संकटपूर्ण बिक्री से बचाने में मदद मिलेगी। किसानों को पता रहेगा कि सरकार उनकी पूरी फसल के लिए तय दाम पर खड़ी है, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमिलनाडु के तोतापुरी आम उत्पादक किसानों के लिए भी राहत भरा फैसला लिया है। वर्ष 2026 के दौरान 96,879 मीट्रिक टन तोतापुरी आम की खरीद को बाजार हस्तक्षेप योजना (के तहत मंजूरी दी गई है। तमिलनाडु में यह पूरी खरीद बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत की जाएगी। तोतापुरी आम का बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,545.41 रु. प्रति क्विंटल तय किया गया है। इस हस्तक्षेप मूल्य के जरिये सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आम उत्पादक किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिले, और उन्हें बाजार में अचानक गिरते भावों के कारण घाटे में अपनी फसल बेचने की मजबूरी न हो। यह कदम किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम दिलाने और उनकी आय को स्थिर रखने में मदद करेगा।

केंद्र सरकार द्वारा खोपरा और तोतापुरी आम की इतनी बड़ी मात्रा में खरीद की मंजूरी और हजार करोड़ रु. से अधिक के एमएसपी मूल्य की सुरक्षा, तमिलनाडु के किसानों के लिए बड़ी राहत है।

फ्लूट मेडिटेशन कार्यक्रम 11 जुलाई को

भोपाल। आज जहाँ लोगों में जीवन शैली की वजह से तनाव, थकान तथा मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की लत के चलते एकाग्रता, माइंडफुलनेस में कमी और अटेंशन-डेफिसिट/हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर जैसे विकार आम बात हो गए हैं। दूसरी तरफ़ इनसे बचने और बेहतर तरह से इनका सामना करने के लिए नित नए प्रयोग भी हो रहे हैं। ऐसा ही एक प्रभावी कार्यक्रम जाटखेड़ी स्थित स्टूडियो ब्रीद एंड बैलेंस में 11 जुलाई को शाम 4 बजे आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में लाइव फ्लूट वादन के साथ प्रतिभागियों को मेडिटेशन कराया जाएगा। आयोजक निशा ने बताया कि हमारी कोशिश रहती है कि हमसे जुड़े लोगों को बेहतर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य और स्वस्थ मनोरंजन की ओर उन्मुख करें और फ्लूट मेडिटेशन का एक कार्यक्रम पहले भी हमारे यहाँ किया जा चुका है , जिस से लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचा। कार्यक्रम में बाँसुरी वादक नितेश मांगरोले भारतीय शास्त्रीय संगीत के कुछ रागों (जैसे राग भूपाली) के स्वर बांसुरी पर लाइव बजाएँगे जो मानसिक तनाव को कम करने और एकाग्रता बढ़ाने में बेहद कारगर सिद्ध हो सकते हैं।

नर्मदा जल समझौते में मध्य प्रदेश के साथ हुआ अन्याय : भाकपा

भोपाल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने विगत 30 वर्षों से लंबित नर्मदा जल विवाद के अब हुए समझौते को मध्य प्रदेश के अन्याय पूर्ण कार्रवाई बताते हुए इसके जिम्मेदार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से इस्तीफ़ा देने की मांग की है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मध्य प्रदेश राज्य सचिव कॉमरेड शैलेन्द्र शैली ने बताया कि सरदार सरोवर परियोजना के तहत निर्मित बांध में मध्य प्रदेश की 55 प्रतिशत ज़मीन डूबी है। इसके लिए मध्य प्रदेश ने गुजरात से 7669 करोड़ रुपए के मुआवज़े का दावा किया था, लेकिन अब मुआवजा तो मिलना रहा दूर,उल्टे मध्य प्रदेश को गुजरात को 550 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा।मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहद चिंताजनक है। मध्य प्रदेश सरकार को बार बार कर्ज़ लेना पड़ता है।उसके बावजूद मध्य प्रदेश को 550 करोड़ रुपए का भुगतान करने का समझौता होना मध्य प्रदेश के साथ अन्याय है। जाहिर है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भाजपा की गुजरात लॉबी के दबाव में आकर इस तरह समझौता करके मध्य प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया है।इसके जिम्मेदार मुख्य मंत्री को इस्तीफ़ा देना चाहिए ।

मध्य प्रदेश कर्ज के दलदल में, 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज : जीतू पटवारी

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बदहाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश को कर्ज के दलदल में धकेल दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने एक बार फिर 3,600 करोड़ रुपये का नया कर्ज लिया है, जिसके बाद प्रदेश पर कुल कर्ज 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। श्री पटवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियां जारी कर बाजार से 3,600 करोड़ रुपये का नया कर्ज लिया है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 में सरकार अब तक 12,800 करोड़ रुपये की उधारी ले चुकी है। सरकार ने पूरे वित्तीय वर्ष में 78,500 करोड़ रुपये उधार लेने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 16.30 प्रतिशत राशि अभी शुरुआती महीनों में ही उधार ले ली गई है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक प्रदेश पर 4,88,714.17 करोड़ रुपये का कर्ज था। नई उधारी के बाद यह आंकड़ा 5 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। सबसे गंभीर बात यह है कि मध्य प्रदेश पर चढ़ा कर्ज अब राज्य सरकार के वार्षिक बजट से भी अधिक हो चुका है। यह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की आर्थिक नीतियों की विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। श्री पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री बताएं कि आखिर प्रदेश को लगातार कर्ज के सहारे क्यों चलाया जा रहा है? इतना भारी कर्ज लेने के बावजूद किसानों को खाद और सिंचाई नहीं मिल रही, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है तथा विकास कार्य ठप पड़े हैं। यदि कर्ज विकास के लिए लिया जा रहा है तो उसका परिणाम जनता को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि सरकार को अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा केवल कर्ज के ब्याज के रूप में चुकाना पड़ रहा है। जनता के टैक्स का पैसा विकास पर खर्च होने के बजाय ब्याज चुकाने में जा रहा है। इसका बोझ आने वाली पीढ़ियों पर डाला जा रहा है।

स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए वैल्यू एडेड कोर्स का चयन अनिवार्य

विद्यार्थियों को रोजगार, नैतिक मूल्य, पर्यावरण एवं कौशल आधारित शिक्षा से जोड़ने की पहल

भोपाल (नप्र)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए वैल्यू एडेड कोर्स, संवैधानिक, मानवीय एवं नैतिक मूल्य तथा पर्यावरण शिक्षा एवं स्थिरता आधारित पाठ्यक्रमों का चयन अनिवार्य किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी करीकुलम एण्ड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम्स (सीसीएफपीजी), जून-2024 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के नवीन अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक स्नातकोत्तर विद्यार्थी को द्वितीय सेमेस्टर में 2 क्रेडिट पॉइंट का एक वैल्यू एडेड पाठ्यक्रम लेना होगा। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न विषय समूहों अंतर्गत पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें रोजगार एवं उद्यमिता कौशल, योग एवं ध्यान द्वारा तनाव प्रबंधन, पर्यावरण मनोविज्ञान, शोध लेखन कौशल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, नवाचार एवं उद्यमिता जैसे विषय शामिल हैं। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों को विषय ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक कौशल, नैतिक मूल्यों, नवाचार क्षमता एवं रोजगारपरक दक्षताओं से जोड़ना है। सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक आवश्यकता और विषय की उपयोगिता के अनुसार इन पाठ्यक्रमों के चयन में आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए।

589.63 हैक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण से मुक्त

सागौन रूट-शूट से होगा पुनर्वनीकरण, अतिक्रमणकारियों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी

भोपाल (नप्र)। धार वन मंडल ने वन भूमि संरक्षण एवं अतिक्रमण नियंत्रण अभियान के तहत जनवरी से मई 2026 के बीच कड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 589.63 हैक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। यह कार्रवाई वन विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन, पुलिस, ग्राम वन समितियों तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से 7 वन परिक्षेत्रों में की गई।

विभागीय कार्रवाई में वन परिक्षेत्र धार में 100.55 हैक्टेयर, धामनोद में 35.10हैक्टेयर, मांडव में 50.78 हैक्टेयर, सरदारपुर में 50.62 हैक्टेयर, टांडा में 93.76 हैक्टेयर, बाग में 202.82 हैक्टेयर तथा कुक्षी में 56.00 हैक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। धार वन मंडल में कुल 589.63 हैक्टेयर वन भूमि पुनः वन विभाग के संरक्षण में लाई गई। अभियान का उद्देश्य वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर उसका पुनर्वनीकरण करते हुए प्राकृतिक वन संपदा का संरक्षण एवं संवर्धन करना है। अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि पर सागौन रूट-शूट की तैयारी की जा रही है। इसके लिए अधिकारियों एवं मैदानी कर्मचारियों को वैज्ञानिक पद्धति से सागौन रूट-शूट रोपण, पौध संरक्षण एवं रखरखाव का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

वन विभाग ने आमजन से अपील की है कि वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें। वन भूमि सार्वजनिक एवं प्राकृतिक संपदा है, जिसका संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। वन मंडल अधिकारी श्री विजयानंथम टी.आर. ने चेतावनी दी है कि वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति वन भूमि पर अतिक्रमण करता है अथवा ऐसा करने का प्रयास करता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा अन्य प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के तहत आपराधिक प्रकरण वन विभाग के साथ पुलिस में भी एफआईआर भी दर्ज कराई जायेगी।

शहडोल में हुआ है गजब का घोटाला

गड्ढों को तालाब बताकर निकाल लिए 25-25 लाख रुपए

शहडोल(नप्र)। मध्य प्रदेश के शहडोल में तालाब निर्माण के नाम पर करोड़ों के घोटाले का मामला सामने आया है। आरोप है कि पुराने गड्ढों, सड़क खुदाई के दौरान बने गड्ढों को ही नया तालाब बता कर पैसे डीएमएफ फंड से निकाल लिए गए और बंदरबांट कर ली है।

तालाब के निर्माण पर हुए करोड़ों खर्च- शहडोल जिले में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड से तालाब निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। साल 2022-23 की कार्ययोजना में डीएमएफ मद से तालाब निर्माण, घाट निर्माण और सौंदर्यीकरण के 43 प्रोजेक्ट मंजूर किए गए, जिनके लिए 7.48 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। इनमें 24 नए तालाब निर्माण की परियोजनाएं थीं, जिनका बजट 5.75 करोड़ रुपए था।

एक तालाब की औसत लागत 25 लाख रुपए- डीएमएफ के रिकॉर्ड के अनुसार, एक तालाब की औसत लागत 25 लाख रुपए है। नए तालाब निर्माण के नाम पर स्वीकृत आधे से अधिक प्रोजेक्ट ऐसे तालाबों पर हैं, जो वर्षों से पहले ही अस्तित्व में हैं । यानी जिन स्थानों पर नए तालाब बनने का दावा किया गया, वहां नया निर्माण नहीं हुआ है। इसी तरह गड्ढों को तालाब बताकर 25-25 लाख रुपए का भुगतान ले लिया गया।

हाईवे किनारे खोदे गए गड्ढे को तालाब घोषित कर दिया

इसी तरह जयसिंहनगर ब्लॉक के जोरा गांव के पास रीवा-शहडोल हाईवे निर्माण के दौरान खोदे गए एक गड्ढे को ही तालाब घोषित कर दिया गया। हाईवे के लिए मुरम निकालने से सड़क किनारे करीब 2 से ढाई एकड़ का बड़ा गड्ढा बन गया था। इसके लिए 25 लाख रुपए आवंटित किए गए। जयसिंहनगर ब्लॉक की बरना पंचायत के झिरिया में 20 साल पुराना तालाब है। इस पुराने तालाब के स्थान पर 20.56 लाख की लागत से नवीन तालाब निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी गई। पुराने तालाब को ही नया बढ़कर राशि निकाल कर बांट ली गई। इसके अलावा इन पंचायतों में तालाब निर्माण पर निकाले गए पैसे पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहले से मौजूद स्ट्रक्चर को ही तालाब बताकर पैसा निकाल लिया गया।

व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ प्रबुद्ध नागरिक जाएंगे हाईकोर्ट

भोपाल। भूमि विकास नियम-2012 में संशोधन कर आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को अनुमति देने की सरकारी तैयारियों के खिलाफ भोपाल के जागरूक नागरिकों और संस्थाओं ने मोर्चा खोल दिया है। इस विवादास्पद संशोधन के विरोध में अरेरा कॉलोनी के रहवासियों की संस्था प्रयास जन कल्याण समिति द्वारा एक अहम बैठक और गहन चर्चा का आयोजन किया गया। बैठक में शामिल नागरिकों और विशेषज्ञों ने इस नीतिगत फेरबदल को रहवासियों के शांतिपूर्ण जीवन और कानूनी व्यवस्था पर सीधा प्रहार बताया है।

मास्टर प्लान का उल्लंघन और बुनियादी सुविधाओं पर अतिरिक्त दबाव: अपर्णा वशिष्ठ

करीब दो घंटे चली इस चर्चा में सामने आए कानूनी, तकनीकी और व्यावहारिक पहलुओं के आधार पर समिति की अध्यक्ष अपर्णा वशिष्ठ ने 20 बिंदुओं की एक विस्तृत आपत्ति तैयार की है, जिसे शासन को भेजा जा रहा है।

चर्चा में रहवासियों ने स्पष्ट किया कि यदि यह प्रस्तावित संशोधन लागू होता है, तो मूल स्वरूप प्रभावित होगा: आवासीय क्षेत्रों का मूल ढांचा पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। रिहायशी इलाकों में अस्पताल, होटल, कोचिंग सेंटर, कार्यालय और शोरूम जैसी व्यावसायिक गतिविधियों का अनियंत्रित विस्तार होगा।

बुनियादी ढांचे पर संकट: व्यावसायिक गतिविधियों के कारण स्थानीय यातायात, पार्किंग, जलापूर्ति, ड्रेनेज और अन्य बुनियादी नागरिक सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा।

नियमों का विरोधाभास: बिल्डर-अफसरों के दबाव में हो रहा कार्य, नियमों का मखौल उड़ा रही सरकार: पूर्णेन्दु शुक्ल

चर्चा में विशेष रूप से भाग लेते हुए वरिष्ठ पत्रकार एवं जनहित याचिकाकर्ता पूर्णेन्दु शुक्ल ने सरकार की मंशा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से राजनीतिज्ञों, रियल एस्टेट एजेंटों और अफसरों के दबाव में कार्य कर रही है। चुनिंदा लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए ही नियमों में यह बदलाव किया जा रहा है, जो यदि लागू हुआ तो रहवासी कॉलोनियाँ रहने लायक नहीं रह जाएंगी। उन्होंने नगर निगम और सरकार के दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाते हुए कहा-जब सुप्रीम कोर्ट के कड़े आदेशों के कारण नगर निगम खुद भवन अनुज्ञा के विपरीत हुए अवैध निर्माण, अतिक्रमण और दुकान बनाने वालों को लगातार नोटिस थमा रहा है और आवासीय लीज़ के मकानों पर बने कमर्शियल ठिकानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है, तो फिर सरकार नियमों में ऐसा पिछला दरवाजा खोलने वाला फेरबदल कैसे कर सकती है? पूर्णेन्दु शुक्ल ने बैठक में जानकारी दी कि उनके समूह की ओर से दायर एक (जनहित याचिका) में माननीय उच्च न्यायालय ने गत वर्ष ही अंतरिम रिलीफ प्रदान की है। इस आदेश के तहत कोर्ट ने नगर निगम के नियमों और क्षेत्र के मास्टर प्लान के विरुद्ध किए जा रहे ऐसे समस्त अनधिकृत निर्माणों पर पहले ही रोक लगा रखी है।

विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए 8 से 15 जुलाई तक महाविद्यालयों में लगेगा 'प्रवेश मेला'

अतिरिक्त सीएलसी राउंड में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए मिशन मोड में चलेगा अभियान

भोपाल (नप्र)। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर अधिक से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 8 से 15 जुलाई 2026 तक प्रवेश मेला आयोजित किया जा रहा है। अतिरिक्त सीएलसी राउंड के दौरान प्रवेश प्रक्रिया को गति देने एवं पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए यह विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।

प्रवेश मेले के दौरान महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को एक ही स्थान पर पंजीयन, चॉइस फिलिंग एवं संशोधन, दस्तावेज सत्यापन, सीट आवंटन संबंधी मार्गदर्शन तथा शुल्क भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे पात्र विद्यार्थी उसी दिन अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। महाविद्यालयों में प्रवेश मेला प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होगा।

महाविद्यालयों द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध लंबित पंजीयन, सत्यापन, प्रवेश प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद भी शुल्क जमा नहीं करने वाले विद्यार्थियों की सूची का परीक्षण कर उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जाएगा। विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान कर उन्हें प्रवेश लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिन पाठ्यक्रमों एवं संकायों में रिक्त सीटों की संख्या अधिक है, वहां विशेष प्रयास किए जाएंगे। विद्यार्थियों को उपलब्ध पाठ्यक्रमों, विषय चयन एवं चॉइस संशोधन के संबंध में आवश्यक परामर्श प्रदान किया जाएगा। साथ ही स्थानीय विद्यालयों, जनप्रतिनिधियों, पालकों एवं पूर्व विद्यार्थियों के सहयोग से प्रवेश जन-जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।

प्रत्येक महाविद्यालय में प्राचार्य की निगरानी में प्रतिदिन प्रवेश की समीक्षा की जाएगी तथा विभागवार एवं संकायवार लक्ष्य निर्धारित कर कार्यवाही की जाएगी। जिला नोडल अधिकारी अधिक रिक्त सीट वाले महाविद्यालयों की विशेष निगरानी करेंगे और आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएंगे। समस्त महाविद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि प्रवेश मेला केवल औपचारिक आयोजन न होकर अधिकतम प्रवेश, उसी दिन प्रवेश की कार्यपद्धति पर संचालित किया जाए, जिससे अतिरिक्त सीएलसी राउंड में अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश का लाभ मिल सके।

संपादकीय

ई-20 ईंधन को लेकर शंकाएं

मोदी सरकार द्वारा स्वचालित वाहनों में ई- 20 ईंधन के उपयोग को लागू किए जाने को लेकर कई तरह की शंकाएं और सवाल लोगों के मन हैं, लेकिन सरकार इन सभी का कोई समाधानकारक जवाब नहीं दे पा रही है। यहां तक पहले सरकार ने कोर्ट में कहा कि यह केवल एक 'एक्सपेरिमेंट' है, लेकिन बाद में वह इससे भी मुकर गई। ऐसे में प्रश्न यह उठ रहा है कि सरकार कच्चे तेल का आयात बिल घटाकर कहीं ऐसे प्रयोग तो नहीं करने जा रही है, जो आम लोगों की गाड़ियों के लिए भारी नुकसानदेह हो। लोगों को लेने के देने पड़ जाएं। सवाल यह भी है कि अगर ई-20, ई-10 और ई-0 वाहनों के लिए सुरक्षित है, तो फिर अलग से ई-20-प्रमाणित (सर्टिफाइड) वाहन बनाने और उन्हें अनिवार्य करने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल ये तमाम सवाल ई 20 ईंधन के उपयोग के समर्थन में नई दिल्ली में आयोजित एक पत्रकारवार्ता के बाद तेजी से उठे हैं। ई-20 ईंधन पर मोदी सरकार की सफ़ाई के बाद भी कई सवालों के जवाब अभी भी अनुत्तरित हैं। मसलन पुराने वाहनों की सुरक्षा, कम माइलेज के बावजूद समान क़ीमत, कृषि सब्सिडी और भूजल की लागत, भंडारण से जुड़े जोखिम, नीति आयोग की हटाई गई रिपोर्ट और उपभोक्ताओं को मुआवज़े जैसे मुद्दों पर सरकार ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। नई दिल्ली में 4 जुलाई को आयोजित सरकारी प्रेस ब्रीफिंग असल में ई' 20 ईंधन को लेकर उठ रही उंगलियों के डेमेज कंट्रोल की कोशिश थी। इसमें पेट्रोलियम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, ऑटोमोबाइल उद्योग के प्रतिनिधियों और तेल विपणन कंपनियों के अधिकारियों ने बारी-बारी से उपभोक्ताओं की चिंताओं को 'रेज बेट' (यानी लोगों को भड़काने के लिए फैलाई जा रही सामग्री) बताकर खारिज किया, जबकि ई-20 कार्यक्रम के आर्थिक लाभों को बढ़-चढ़कर पेश किया गया। यह ब्रीफिंग तब आयोजित की गई जब देशभर से ई-20 ईंधन को लेकर शिकायतें सामने आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान यह खबर आई थी कि सरकार ने ई-20 को एक 'प्रयोग' (एक्सपेरिमेंट) बताया है, हालांकि सरकार अब इस दावे से इंकार कर रही है। ब्रीफिंग के दौरान अधिकारियों ने लगातार यह संदेश देने की कोशिश की कि पूरे देश में ई-20 का लागू होना हर दृष्टि से आसान और सभी के लिए लाभकारी है। लेकिन हकीकत इससे कहीं अधिक जटिल है. ई-20 को लेकर कीमत, सुरक्षा मानकों, नियामकीय (रेगुलेटरी) एकरूपता और उपभोक्ताओं को होने वाले नुकसान की भरपाई जैसे कई महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिन पर इस पूरी प्रेस ब्रीफिंग में कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। प्रेस ब्रीफिंग में जो दावे किए गए, वह नियामकीय व्यवस्था से मेल नहीं खाते। क्योंकि नियमों के मुताबिक अप्रैल 2023 के बाद निर्मित सभी वाहनों का ई-20-सर्टिफाइड होना अनिवार्य है। इसके लिए अलग मटेरियल कंपैटिबिलिटी और इंजन ट्यूनिंग संबंधी मानक तय किए गए हैं। यदि वास्तव में ई-20 बिना किसी बदलाव के सभी पुराने वाहनों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है, तो फिर अलग से ई-20 प्रमाणन व्यवस्था बनाने, नए तकनीकी मानक तय करने और वाहन निर्माताओं को अपने उत्पादन तंत्र में बदलाव (रीटूलिंग) करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? या तो नियामकीय व्यवस्था जरूरत से ज्यादा सख्त बनाई गई है, या फिर 2023 से पहले बने वाहनों के लिए ई-20 की सुरक्षा को लेकर अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता। यह मुद्दा अब राजनीतिक भी बनता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 'एक मंत्री कुछ कहता है, तो दूसरा मंत्री कुछ और। ई-20 ईंधन पर सरकार झूठ बोल रही है। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में श्वेतपत्र जारी करने की मांग की है।

नजरिया

कुमार कृष्णन

लेखक स्तंभकार हैं।

भूमि अधिग्रहण जवाबदेही व जनभागीदारी का विषय

भारत में विकास की गति जितनी तेज हुई है, भूमि का प्रश्न भी उतनी ही तीव्रता से राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में आया है। सड़कें, औद्योगिक गलियारे, बिजलीघर, स्मार्ट सिटी, सैटेलाइट टाउनशिप और पर्यटन परियोजनाएँ आधुनिक भारत की विकास-यात्रा के प्रतीक हैं। किंतु इनके साथ एक मूलभूत प्रश्न लगातार उठ रहा है–विकास की कीमत कौन चुकाएगा? क्या विकास केवल निवेश, उत्पादन और आधारभूत संरचना का विस्तार है, या उसमें उन लोगों की आजीविका, संस्कृति और संवैधानिक अधिकार भी शामिल हैं, जिनकी भूमि पर विकास की इमारत खड़ी होती है?

यह बहस अब किसी एक राज्य तक सीमित नहीं रही। बिहार के पूर्वी चंपारण के पिपराकोठी में प्रस्तावित वाटर पार्क, राज्य की ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप योजना, बांका में प्रस्तावित परमाणु बिजलीघर और झारखंड के गोड्डा जिले के मोतिया में औद्योगिक परियोजनाओं को लेकर उठे विवाद एक समान संदेश देते हैं कि विकास और लोकतंत्र के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जनविश्वास है। जब प्रभावित लोगों को लगता है कि निर्णय उनकी भागीदारी के बिना लिए जा रहे हैं, तब सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाएँ भी विरोध और अविश्वास का कारण बन जाती हैं।

यह विडंबना ही है कि जिस चंपारण ने 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह के माध्यम से संवाद, न्याय और अहिंसक प्रतिरोध की मिसाल कायम की थी, वहीं आज भूमि का प्रश्न फिर सामाजिक और राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। पिपराकोठी में प्रस्तावित वाटर पार्क को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच विवाद ने स्पष्ट किया है कि विकास की प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास का अभाव कितना गंभीर संकट पैदा कर सकता है।

किसानों का दावा है कि जिस भूमि पर उनके परिवार पीढ़ियों से खेती करते आए हैं, उसे सरकारी भूमि बताकर उनकी आजीविका पर संकट खड़ा किया जा रहा है। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि संबंधित भूमि सरकारी अभिलेखों में दर्ज है और परियोजना के लिए सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। लोकतंत्र में दोनों पक्षों के दावों की निष्पक्ष जांच ही समाधान का आधार हो सकती है। यदि किसानों के पास राजस्व रसीदें, दाखिल-खारिज अथवा अन्य वैध दस्तावेज हैं, तो उनकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। उसी प्रकार प्रशासन को भी अपने अभिलेख सार्वजनिक कर पारदर्शिता का परिचय देना चाहिए। ऐसे विवादों का सबसे विश्वसनीय समाधान तथ्यों और खुले संवाद से ही निकल सकता है।

यह विवाद तब और व्यापक हो गया जब सांसद सुधाकर सिंह किसानों के समर्थन में विवादित भूमि पर ट्रैक्टर चलाने पहुँचे और उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई। इसके बाद सांसद पप्पू यादव भी आंदोलनरत किसानों के बीच पहुँचे और संघर्ष को संसद से न्यायपालिका तक ले जाने की बात कही। इन घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया कि भूमि का प्रश्न अब केवल स्थानीय प्रशासनिक विवाद नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जवाबदेही और जनभागीदारी का विषय बन चुका है। कमोबेश यही स्थिति बिहार की ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप योजना में भी दिखाई देती है। सरकार का तर्क है कि तेजी से बढ़ते शहरी दबाव के बीच आधुनिक उपग्रह नगरों का विकास समय की आवश्यकता है। इससे

रोजगार, निवेश और आधारभूत संरचना का विस्तार होगा। लेकिन जिन किसानों की भूमि इन योजनाओं के दायरे में आती है, उनके लिए खेत केवल आर्थिक संपत्ति नहीं, बल्कि जीवन, पहचान और भविष्य की सुरक्षा का आधार हैं। कई स्थानों पर मास्टर प्लान लागू होने के बाद भूमि के उपयोग और खरीद-बिक्री पर लगे प्रतिबंधों ने किसानों की आशंकाएँ और बढ़ा दीं। बाद में सरकार ने कुछ राहत अवश्य दी, किंतु अविश्वास पूरी तरह समाप्त नहीं हो सका।

वास्तव में किसी भी विकास परियोजना की सफलता केवल उसके आर्थिक आकार से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि प्रभावित समुदाय स्वयं को उसका सहभागी महसूस करता है या नहीं। लोकतंत्र में विकास की वैधता केवल सरकारी स्वीकृतियों से नहीं, बल्कि सामाजिक स्वीकार्यता से भी निर्मित होती है। जहाँ संवाद कमजोर पड़ता है, वहाँ अविश्वास जन्म लेता है; और जहाँ विश्वास टूटता है, वहाँ विकास का रास्ता भी कठिन हो जाता है।

भूमि का प्रश्न बिहार तक सीमित नहीं है। झारखंड के गोड्डा जिले के मोतिया और बिहार के बांका जिले में प्रस्तावित परमाणु बिजलीघर को लेकर भी लंबे समय से बहस जारी है। एक ओर ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन की आवश्यकता है, तो दूसरी ओर किसानों और आदिवासी समुदायों की आजीविका, पर्यावरण और संवैधानिक अधिकारों की चिंता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बांका जिले के बेलहर क्षेत्र में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा परियोजना को लेकर स्थानीय स्तर पर वर्षों से आशंकाएँ व्यक्त की जाती रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित क्षेत्र में उपजाऊ कृषि भूमि, जलस्रोत और प्राकृतिक संसाधन हैं, जिन पर हजारों परिवारों की आजीविका निर्भर करती है। दूसरी ओर सरकार का तर्क है कि बिहार की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को देखते हुए दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए ऐसी परियोजनाएँ आवश्यक हैं और अभी अधिकांश प्रक्रियाएँ प्रारंभिक स्तर पर हैं।

ऊर्जा की आवश्यकता पर कोई विवाद नहीं हो सकता। लेकिन यह प्रश्न अवश्य उठता है कि क्या ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा को एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा किया जाना चाहिए? क्या परियोजना के लिए वैकल्पिक स्थलों का पर्याप्त अध्ययन किया गया है? क्या कम उपजाऊ भूमि, विकेंद्रीकृत ऊर्जा उत्पादन, सौर ऊर्जा या अन्य विकल्पों का तुलनात्मक आकलन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है? लोकतंत्र में ऐसे प्रश्न विकास-विरोध नहीं, बल्कि बेहतर और उत्तरदायी विकास की अपेक्षा हैं।

भारत का अनुभव बताता है कि बड़े बांधों, खनन क्षेत्रों, औद्योगिक परियोजनाओं और राजमार्गों के लिए हुए व्यापक विस्थापन ने केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संकट भी उत्पन्न किए हैं। केवल आर्थिक मुआवजा किसी परिवार की उस क्षति की भरपाई नहीं कर सकता, जो उसकी जमीन, सामाजिक पहचान और पीढ़ियों से जुड़े जीवन-संबंधों के टूटने से होती है। किसान के लिए खेत बाजार में बिकने वाली संपत्ति भर नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व, सम्मान और भविष्य की सुरक्षा का आधार होता है। यही कारण है कि भूमि का प्रश्न केवल राजस्व प्रशासन का विषय नहीं, बल्कि संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय से भी जुड़ा है। विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा, स्थानीय समुदायों और संवैधानिक अधिकारों की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण मानी गई है कि विकास की दिशा लोगों की भागीदारी और विश्वास के साथ तय हो। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वह विकास और अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने का मार्ग खोजता है, टकराव का नहीं। यहीं महात्मा गांधी का चंपारण आज भी नई अर्थवत्ता के साथ सामने आता है। गांधी ने चंपारण में किसानों की पीड़ा को केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया था। उन्होंने गाँव-गाँव जाकर तथ्य जुटाए, किसानों और प्रशासन–दोनों की बात सुनी और सत्य को संघर्ष का आधार बनाया। यही कारण है कि चंपारण सत्याग्रह केवल एक आंदोलन नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक आचरण की ऐसी मिसाल बना, जिसमें संवाद, पारदर्शिता और न्याय एक-दूसरे के पूरक थे। आज जब उसी धरती पर भूमि से जुड़े प्रश्न फिर राष्ट्रीय बहस का विषय बन रहे हैं, तब गांधी की कार्यपद्धति पहले से अधिक प्रासंगिक दिखाई देती है।

भूमि अधिग्रहण अथवा लैंड पूलिंग से जुड़ी प्रत्येक परियोजना में सामाजिक प्रभाव आकलन, पर्यावरणीय मूल्यांकन, ग्राम सभाओं और स्थानीय निकायों की प्रभावी भागीदारी, सभी अभिलेखों की सार्वजनिक उपलब्धता, स्वतंत्र जनसुनवाई तथा पुनर्वास और आजीविका सुरक्षा को नीति का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए। केवल भूमि मालिकों ही नहीं, बल्कि बटाईदारों, खेतिहर मजदूरों और कृषि पर आश्रित अन्य परिवारों के हितों का भी समुचित संरक्षण आवश्यक है।

इसके साथ ही आंदोलनकारी समूहों और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। जनभावनाओं का सम्मान करते हुए संघर्ष को तथ्यों, संविधान और अहिंसक लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भीतर रखना आवश्यक है। भारत के सामने वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि विकास हो या न हो। प्रश्न यह है कि विकास का स्वरूप कैसा हो। क्या वह लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ेगा या लोगों के ऊपर से गुजर जाएगा? लोकतंत्र में विकास की सफलता केवल परियोजनाओं के उद्घाटन, निवेश के आकार या उत्पादन के आँकड़ों से नहीं मापी जाती। उसकी वास्तविक कसौटी यह है कि क्या सबसे कमजोर नागरिक भी स्वयं को उस विकास का सहभागी महसूस करता है।

आज आवश्यकता किसी एक पक्ष की जीत की नहीं, बल्कि ऐसी विकास-दृष्टि की है जो खेत और कारखाने, गाँव और शहर, उद्योग और पर्यावरण, विज्ञान और मानवीय संवेदना के बीच संतुलन स्थापित कर सके। भूमि केवल राजस्व का विषय नहीं, जीवन का आधार है; और विकास केवल निर्माण का नाम नहीं, बल्कि विश्वास अर्जित करने की सतत लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। भारत की विकास-यात्रा तभी सफल मानी जाएगी, जब प्रगति और न्याय साथ-साथ चलेंगे तथा विकास और लोकतंत्र एक-दूसरे के पूरक बनेंगे, प्रतिस्पर्धी नहीं।

तकनीक

डॉ. मनीष जैसल

लेखक मीडिया शिक्षक हैं।

अपने लिए एल्गोरिदम की भाषा को समझना जरूरी

हम अपने मोबाइल की स्क्रीन को छूते हैं, लेकिन शायद ही कभी यह सोचते हैं कि हमारी स्क्रीन हमें किस तरह छू रही है। हर सुबह जागने के बाद दिखाई देने वाली खबरें, सोशल मीडिया की पोस्ट, वीडियो, विज्ञापन और सुझाव महज़ डिजिटल सामग्री के साथ साथ हमारे व्यवहार का प्रतिबिंब भी बन चुके हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि इंटरनेट पर जो कुछ भी हमारे सामने आता है, वह हमारी पसंद का परिणाम है। हालाँकि यह बात पूरी तरह गलत भी नहीं है । सच यह है कि डिजिटल दुनिया में हमारी पसंद और एल्गोरिदम के बीच एक निरंतर संवाद चलता रहता है। हम उसे निर्देश देते हैं, और वह धीरे-धीरे हमारे देखने, पढ़ने और सोचने के ढंग को आकार देने लगता है। इस संवाद की भाषा को समझे बिना डिजिटल युग को समझना संभव नहीं।

पिछले एक दशक में 'एल्गोरिदम' शब्द तकनीकी प्रयोगशालाओं से निकलकर सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। पहले यह कंप्यूटर विज्ञान का विषय था, आज यह लोकतंत्र, पत्रकारिता, शिक्षा, बाज़ार और संस्कृति सभी पर असर डालने वाली शक्ति बन चुका है। चुनावों की चर्चा हो, फेक न्यूज़ का संकट हो, ऑनलाइन खरीदारी हो या मनोरंजन हर जगह एल्गोरिदम मौजूद है।

दरअसल, एल्गोरिदम कोई रहस्यमयी सत्ता नहीं है। यह निर्देशों की ऐसी श्रृंखला है जो उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर निर्णय लेने में मशीन की सहायता करती है। लेकिन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर इसकी भूमिका केवल गणना तक सीमित नहीं रहती। यहाँ एल्गोरिदम यह तय करता है कि अरबों सूचनाओं के बीच आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले क्या पहुँचेगा, कौन-सी खबर आपके ध्यान में आएगी, किस वीडियो की सिफारिश होगी और किन विचारों से आपका सामना होगा।

यहीं से सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। सामान्य धारणा यह है कि एल्गोरिदम हमारी सोच को नियंत्रित करते हैं। यह निष्कर्ष आकर्षक अवश्य है, लेकिन अधूरा है। एल्गोरिदम किसी निर्वात में काम नहीं करते। वे मनुष्य के व्यवहार से सीखते हैं। आप किस समाचार पर अधिक समय बिताते हैं, किस वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं, किन विषयों को बार-बार खोजते हैं, किस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हैं और किन लोगों की बातों को साझा करते हैं–इन सबका लेखा-जोखा डिजिटल प्रणाली लगातार रखती है।

इसलिए यह कहना कि एल्गोरिदम हमें नियंत्रित कर रहे हैं, उतना ही अधूरा है जितना यह कहना कि सारी जिम्मेदारी उपयोगकर्ता की है। यही कारण है कि आज सूचना के संकट को केवल तकनीकी समस्या मानना भूल होगी। जब कोई व्यक्ति लगातार सनसनीखेज़ शीर्षकों पर क्लिक करता है, अपुष्ट सूचनाएँ साझा करता है या उत्तेजक सामग्री को अधिक समय देता है, तो एल्गोरिदम इसे उसकी वास्तविक रुचि मान लेता है। इसके बाद वही सामग्री और अधिक मात्रा में उसके सामने आने लगती है। धीरे-धीरे उपयोगकर्ता को यह भ्रम होने लगता है कि पूरी दुनिया उसी तरह सोच रही है, जैसा वह सोचता है।

इसी स्थिति को समझाने के लिए 'फ़िल्टर बबल' और 'इको चैंबर' जैसी अवधारणाएँ सामने आईं। इनका अर्थ केवल इतना नहीं है कि हमें पसंद की सामग्री दिखाई देती है। असली समस्या यह है कि जो सामग्री हमारी स्थापित धारणाओं को चुनौती दे सकती है, वह धीरे-धीरे हमारी पहुँच से बाहर होने लगती है। असहमति अदृश्य हो जाती है और सहमति सामान्य सत्य प्रतीत होने लगती है।

हालाँकि यहाँ भी सावधानी आवश्यक है। एल्गोरिदम को हर सामाजिक समस्या का खलनायक बना देना आसान है, लेकिन इससे वास्तविक चुनौती छिप जाती है। तकनीक हमारी प्रवृत्तियों को तेज़ कर सकती है, उन्हें जन्म नहीं देती। इसलिए प्रश्न केवल यह नहीं है कि एल्गोरिदम क्या कर रहे हैं; प्रश्न यह भी है कि हम उनके साथ क्या कर रहे हैं।

प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ और पूर्व नीति-निर्माता निक क्लेग ने लिखा है कि 'एल्गोरिदम और उपयोगकर्ता का संबंध टैंगो नृत्य की तरह है; इसमें दोनों साझेदार होते हैं।' यह टिप्पणी इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह उस सरल निष्कर्ष को चुनौती देती है जिसमें सारी जिम्मेदारी मशीन पर डाल दी जाती है।

निक क्लेग यह भी स्वीकार करते हैं कि तकनीकी कंपनियों को अपने एल्गोरिदम के बारे में अधिक पारदर्शी होना चाहिए। उपयोगकर्ताओं को यह समझने का अधिकार है कि उन्हें कोई विशेष सामग्री क्यों दिखाई जा रही है और वे

अपनी डिजिटल प्राथमिकताओं पर अधिक नियंत्रण कैसे स्थापित कर सकते हैं।

आज आवश्यकता एल्गोरिदम से भयभीत होने की नहीं, बल्कि उसकी कार्यप्रणाली को समझने की है। जिस समाज को यह समझ नहीं होगी कि उसकी डिजिटल पसंद किस तरह निर्मित हो रही है, वह धीरे-धीरे सूचना का उपभोक्ता तो बना रहेगा, लेकिन सूचना का सचेत नागरिक नहीं बन पाएगा।

यदि एल्गोरिदम हमारे डिजिटल अनुभव को आकार दे रहे हैं, तो स्वाभाविक प्रश्न है–क्या हमें यह जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि वे ऐसा कैसे करते हैं? आखिर किस आधार पर कोई समाचार हमारी स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिखाई देता है, कोई वीडियो बार-बार सुझाया जाता है या कोई विज्ञापन केवल हमें ही दिखता है? यह प्रश्न तकनीकी जिज्ञासा का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक पारदर्शिता का है।

यहीं से एल्गोरिदमिक पारदर्शिता (Algorithmic Transparency) की अवधारणा महत्त्वपूर्ण हो जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि तकनीकी कंपनियाँ अपना पूरा स्रोत-कोड सार्वजनिक कर दें। बल्कि इसका आशय यह है कि नागरिकों को कम-से-कम इतना पता हो कि उनके सामने सामग्री किन सिद्धांतों के आधार पर लाई जा रही है। यदि किसी प्लेटफ़ॉर्म का उद्देश्य केवल उपयोगकर्ता का ध्यान अधिक समय तक बाँधे रखना है, तो वह स्वाभाविक रूप से उसी सामग्री को प्राथमिकता देगा जो भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करे। लोकप्रिय डॉक्यूमेंट्री The Social Dilemma यह प्रश्न उठाती है कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं के व्यवहार को इस प्रकार प्रभावित करते हैं कि वे धीरे-धीरे डिजिटल निर्भरता के शिकार हो जाएँ।

डिजिटल अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा आज 'अटेंशन इकॉनमी' पर आधारित है। यहाँ सबसे मूल्यवान वस्तु सूचना नहीं, बल्कि मनुष्य का ध्यान है। जितनी देर उपयोगकर्ता किसी प्लेटफ़ॉर्म पर ठहरता है, उतनी ही अधिक उसकी आर्थिक उपयोगिता बढ़ जाती है। इसलिए एल्गोरिदम का लक्ष्य हमेशा ज्ञान का विस्तार करना नहीं होता; कई बार उसका लक्ष्य केवल हमारी स्क्रीन पर बिताया गया समय बढ़ाना होता है। इसका सबसे गहरा असर पत्रकारिता पर दिखाई देता है। कभी समाचार-पत्रों में यह निर्णय संपादक लेते थे कि कौन-सी खबर पहले पृष्ठ पर जाएगी। संपादकीय विवेक पत्रकारिता की आत्मा माना जाता था। आज डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर यह भूमिका बड़ी हद तक एल्गोरिदम निभा रहे हैं।

भारत जैसे लोकतांत्रिक और बहुभाषी समाज में यह प्रश्न और भी जटिल हो जाता है। यहाँ करोड़ों लोग पहली बार इंटरनेट से जुड़े हैं और बड़ी संख्या में नागरिकों के लिए सोशल मीडिया ही समाचार का प्राथमिक स्रोत है। ऐसे में यदि एल्गोरिदम पूर्वाग्रहपूर्ण, अपारदर्शी या केवल व्यावसायिक हितों से संचालित होंगे, तो उसका प्रभाव व्यक्तिगत पसंद से कहीं आगे जाकर सार्वजनिक विमर्श पर पड़ेगा।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इस बहस को एक नया आयाम दिया है। अब एल्गोरिदम केवल सामग्री चुनते नहीं, बल्कि स्वयं सामग्री का निर्माण भी करने लगे हैं। कुछ ही क्षणों में समाचार जैसा दिखने वाला लेख, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की कृत्रिम आवाज़, यथार्थ जैसी प्रतीत होने वाली तस्वीर या पूरी तरह काल्पनिक वीडियो तैयार किया जा सकता है।

ऐसी परिस्थिति में सबसे अधिक आवश्यकता एल्गोरिदमिक साक्षरता की है। जैसे पढ़ना-लिखना आधुनिक नागरिकता की पहली शर्त था, उसी प्रकार डिजिटल युग में एल्गोरिदम को समझना नागरिक चेतना का अनिवार्य हिस्सा बनता जा रहा है। इसका अर्थ तकनीकी विशेषज्ञ बन जाना नहीं है। वास्तव में डिजिटल साक्षरता की शुरुआत इंटरनेट चलाने से नहीं, बल्कि संदेह करने की क्षमता से होती है। लोकतंत्र उन नागरिकों पर नहीं टिकता जो हर सूचना पर विश्वास कर लेते हैं; वह उन नागरिकों पर टिकता है जो सूचना का परीक्षण करते हैं।

यह जिम्मेदारी केवल नागरिकों की भी नहीं है। तकनीकी कंपनियों को अपने एल्गोरिदम के सामाजिक प्रभावों के प्रति अधिक उत्तरदायी होना होगा। सरकारों को ऐसे नियामक ढाँचे विकसित करने होंगे जो नवाचार को बाधित किए बिना पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कर सकें। मशीनें हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन विवेक का स्थान नहीं ले सकतीं। एल्गोरिदम हमें विकल्प दिखा सकते हैं, पर सही विकल्प चुनने की जिम्मेदारी अब भी हमारी ही है।

शायद यही कारण है कि एल्गोरिदम की भाषा को समझना केवल तकनीकी आवश्यकता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक आवश्यकता भी है। जिस दिन नागरिक यह समझने लगेंगे कि उनकी हर क्लिक, हर खोज, हर पसंद और हर साझा की गई सूचना भविष्य के डिजिटल संसार को आकार दे रही है, उसी दिन वे केवल प्लेटफ़ॉर्म के उपयोगकर्ता नहीं रहेंगे, बल्कि डिजिटल लोकतंत्र के सचेत सहभागी बन जाएंगे।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

सुधीर देशपांडे

लेखक व्यंग्यकार हैं।

'मामू' बनाने की कला

आज दो शब्दों पर बात करना है। पहला शब्द कला है। दूसरा मामू। तो कला यानी कला होती है। कला जिसमें होती है वो कलाकार होता है। कलाकार बड़ा मनस्वी होता है। कला संस्कृति का आधार है। याने ये कहा जा सकता है कि कला न होती तो संस्कृति न होती, कलाकार और कला जैसे एक दूसरे के पूरक हैं, वैसे ही संस्कृति और कला भी। कला के बारे में कहा जाता है कि ये पूरी सोलह होती हैं। किसी ने चौंसठ भी कहा है। जो चौंसठ कलाएँ जानता है वह बड़ा ही नहीं तो महान कलाकार हैं। सोलह कलाएं, चंद्रमा की कलाएँ हैं। आदमी, इस चंद्रमा से ज्यादा बड़ा कलाकार हैं। चंद्रमा तो केवल घट-बढ़ की अपनी कला जानता है। वह भी पृथ्वी के साए में रहकर। शायद इसीलिए उसे मामा भी कहा गया है।

मामा हो जाना, कला है या नहीं, नहीं जानता पर मामा बन जाना जरूर कला नहीं है। मामा याने माँ का भाई। माँ का भाई याने अपनी बहन के बच्चों का मामा। वैसे इतिहास में मामा को जो स्थान मिला, वह सही नहीं है। दो मामा तो हमेशा याद आते रहते हैं, एक शकुनि तो दूसरे कंस। कुछ लोगों ने बंदर और चूहे में भी मामा देख लिए, ये उनकी अपनी सोच है। तथापि मामाओं ने अपनी यह छवि धोने की भरपूर कोशिश की है और भांजों ने भी इसका लाभ उठा-ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। खासकर उन भांजों ने जिन्होंने बखत रहते मामा बनाए। बनाने को तो वे काका और बाप भी बनाते देखे गये हैं, पर उन काकाओं और बापों से अलग, मामू बनाने की कला ज्यादा प्रभावी है। इधर पश्चिमी मध्यप्रदेश में तो एक पूरी जनजाति अपने आपको मामा

कहलवाकर खुश होती है तो उधर मध्यप्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी मामा बनकर खुश हैं। मामा फिर भी कला का विषय नहीं हैं। मामा कहलवा कर कृष्ण भी खुश थे। कला है तो मामू बनाना। जो व्यक्ति इस विधा में पारंगत हैं, वह बड़ा कलाकार हैं। मामू किस्म का प्राणी, निहायत ही भोला प्राणी होता है। उसे कोई भी मामू बनाकर चला जाता है। तो यह भी कला नहीं है। क्योंकि वह बेचारा पहले से मामू है ही। जो मामू है वह इस देश की जनता है। जिसे कभी ये तो कभी वो मामू बनाकर चला जाता है और यह मामू बनकर भी खुश रहती है। इस देश में जब से इंटरनेट का चलन बढ़ा है, नये भांजे मैदान में आ जुटे हैं। जो यदा कदा अपनी चतुराई से लोगों को मामू बनाने का काम मुस्तैदी से कर रहे हैं। और एक झटके में वे मामा का खजाना अपने कब्जे में कर लेते हैं और मामू सिर धुनते रह जाते हैं। सरकारी महकमे का मुलाजिम भी इस मामू भांजे की लीला में रत है। जनता मामू बनकर भांजों की खातिर में व्यस्त हैं और भांजे हैं कि मुँह तक भर जाने के बाद भी खाने और बटोरने में व्यस्त हैं। भारत में तभी तो एक भांजे को हजार ब्राह्मणों के बराबर का दर्जा मिला है। भांजे भी मामू के साथ उतनी ही ममता दिखाते हैं। कहते नहीं अघाते कि मामा में तो दोहरा माँपन है। तभी तो मामा कहलाते हैं।

फीफा वर्ल्ड कप 2026

बादल सरोज

लेखक लोकजतन के सम्पादक हैं।

मैसी गॉड, ईश्वर या खुदा नहीं है, हाड़-मांस से बना बंदा है

कल के मुकाबले के असली हीरो इजिप्ट के गोलकीपर मुस्तफा शाबेर हैं। उन्होंने न सिर्फ मैसी की पेनल्टी को रोका बल्कि कम से कम आधा दर्जन ऐसे शॉट्स भी रोके जिनके गोल में तब्दील होने से वे ही रोक सकते थे। मैसी, जिनकी वजह से पांसा पलटा,उनका नम्बर मुस्तफा के बाद ही आता है। मगर बोनस पॉइंट मिलने के चलते सबसे ऊपर पहुँच जाते हैं इजिप्ट के कप्तान मुहम्मद सालाह। इसलिए कि उन्होंने अत्यंत तनाव और बेतहाशा गर्मागर्मी और अपने हताश कोच होसाम हसन के झुंझलाहट भरे बयानों और रेड कार्ड सम्मत आचरण के बीच भी अपना आपा नहीं खोया। हार के बाद वैसी ही प्रतिक्रिया दी जैसी एक खिलाड़ी को देनी चाहिए। उनकी प्रतिक्रिया पढ़ने लायक है।

7 जुलाई की रात का मैच इस फीफा मुकाबले का सबसे कठिन और अब तक का सबसे रोमांचक मैच था। हम जैसे टीम विशेष के पक्षधर पूर्वाग्रहियों के लिए तो यह सचमुच में क़त्ल की रात जैसी थी। मैच के 79वे मिनट तक मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना का पहली बार नॉकआउट मुकाबला खेल रही टीम इजिप्ट से 2-0 से पिछड़ने, इजिप्ट की लौह सुरक्षा दीवार से टकरा-टकरा कर मैसी का बार-बार वापस लौटने के बावजूद आख़िरी 11+2 मिनट में मैच का पूरी तरह बदल जाना सिर्फ फुटबॉल में ही संभव है।

कल के मुकाबले के असली हीरो इजिप्ट के गोलकीपर मुस्तफा शाबेर हैं। उन्होंने न सिर्फ मैसी की पेनल्टी को रोका बल्कि कम से कम आधा दर्जन ऐसे शॉट्स भी रोके जिनके गोल में तब्दील होने से वे ही रोक सकते थे। मैसी, जिनकी वजह से पांसा पलटा,उनका नम्बर मुस्तफा के बाद ही आता है। मगर बोनस पॉइंट मिलने के चलते सबसे ऊपर पहुँच जाते हैं इजिप्ट के कप्तान मुहम्मद सालाह। इसलिए कि उन्होंने अत्यंत तनाव और बेतहाशा गर्मागर्मी और अपने हताश कोच होसाम हसन के झुंझलाहट भरे बयानों और रेड कार्ड सम्मत आचरण के बीच भी अपना आपा नहीं खोया। हार के बाद वैसी ही प्रतिक्रिया दी जैसी एक खिलाड़ी को देनी चाहिए। उनकी प्रतिक्रिया पढ़ने लायक है।

उन्होंने 'मैं वापस आऊँगा' के नसीरुद्दीन शाह के अंदाज़ में कहा कि 'यह हार बहुत दर्दनाक है, लेकिन मिस्र के फैंस को अपनी इस टीम और अपने सपनों पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। हम आगे और मजबूत होकर वापसी करेंगे।' खिलाड़ियों की सराहना करते हुए सालाह बोले कि 'मुझे आप सभी पर बेहद गर्व है। मैदान पर जो कुछ भी हुआ, उसके बावजूद आप सबने अंत तक हार नहीं मानी। हमने इस टूर्नामेंट में इजिप्ट के फुटबॉल का एक नया इतिहास लिखा है।'

उनके अलावा यह मुकाबला याद किया जाएगा अर्जेंटीना की वापसी की जिद और मिस्र के रेगिस्तानों से तपकर आई आंधी के बीच आखिर तक जलाकर रखी उम्मीद की लौ के लिए। विश्व विजेता के राउंड ऑफ़ 16 में ही एलिमिनेट हो जाने की सचमुच की आशंका सामने खड़ी थी। इजिप्ट की टीम अपने पिरामिडों की तरह अडिग और एकदम व्यवस्थित खड़ी थीः बॉल के पेनल्टी एरिया में पहुँचने से पहले ही उसके आधा दर्जन - कई बार तो 7-7 खिलाड़ी अभेद्य दीवार बनाकर खड़े हो जाते थे। मैसी की ड्रिबलिंग स्किल और पास देने की महारत के लिए वे इंच भर जमीन नहीं छोड़ते थे। आख़िरी घंटी बजने में मात्र 11 मिनट शेष हों और स्कोर बोर्ड इजिप्ट 2-अर्जेंटीना 0 पर अटका हो तो .... पसीने सब के छूटते हैं,डर सबको लगता है। मगर डर के आगे जिसे जीत दिखती हो उसे ही अर्जेंटीना कहते हैं। मैसी की अर्जेंटीना।

79वे मिनट पर मैसी के असिस्ट पर क्रिस्टियन रोमेरो पहला गोल जैसे ट्रिगर था। चार मिनट बाद 83वे मिनट में खुद मैसी का सीधा फील्ड गोल मुकाबले को बराबरी पर ले आया। खेल के एक्स्ट्रा टाइम में जाने की संभावना बनने लगी मगर इंजुरी टाइम - खिलाड़ियों के गिरने उठने में लगे समय - के शुरू में ही 90 + 2 मिनट में मार्तिनेज़ के क्रॉस पर एंजो फ़र्नान्डीज के हैडर ने मिस्र के पिरामिड पर लगा जबर ताला चौपट खोल दिया।

दोनों टीम शानदार खेलीं : इजिप्ट ज्यादा अच्छा खेली। आख़िरी 11 मिनट उनके लिए नहीं थे तो नहीं थे। जो इसे रिग्ड, पक्षपातपूर्ण फैसलों और रेफरी की अर्जेंटीना परस्ती का मुकाबला बता रहे हैं वे फुटबॉल के नियमों के मामले में काफी सदाशयी हैं। नामंजूर किया इजिप्ट का गोल सही था या गलत, पेनल्टी देना न देना उचित था या अनुचित यह भावनाओं से नहीं, नियमों और तकनीक से तय होता है। पेनल्टी एरिया में खिलाड़ी के साथ टैक्लिंग और उसे दिया गया चैलेंज यानी धक्कामुक्की पेनल्टी में बदलेगी या नहीं यह इस बात पर मुनस्सर करता है कि बॉल को पहले किसने छुआ था। डिफेंडर के कब्जे में थी तो नहीं मिलेगी, आक्रामक खिलाड़ी के पांवों में थी तो बिल्कुल मिलेगी। जिन्हें अब भी संदेह है वे रीप्ले देख लें।

बेईमानी असंभव नहीं है। खासकर तब जब हजारों - शायद लाखों - करोड़ डॉलर जिस खेल में दांव पर लगे हों, अर्जेंटीना के हारने पर जिसकी व्यूअरशिप धड़ाम से गिर जाने की पक्की गारंटी हो, तब हैण्ड ऑफ़ गॉड की तरह कॉर्पोरेट प्रायोजित स्लिप हो सकती है, की जा सकती है। मगर बेईमानी हुई है इसे सीरियसली मानने वालों से क्षमा, कांस्पीरेसी थ्योरिस्ट्स से सॉरी के साथ यही कहना है कि ऐसा मानकर चलना कुछ ज्यादा ही सन्देही होना है।

एक तो इसलिए कि अब एक अकेला सब पर भारी नहीं होता - यानि अकेले रेफरी के हाथ में सब कुछ नहीं होता। वी ए आर की टीम अलग होती है और इसके रेफरीज - वीडियो असिस्टेंट रेफरीज - अलग होते हैं और कंप्यूटर आधारित तकनीक नापजोख के मामले में मिलीमीटर तक की शुद्धता जांचने के बाद फैसला देती है।

दूसरे यह कि मैच रेफरी चम्पत राय के फूफा नहीं हैं। वे विश्व फुटबॉल के सम्मानित रेफरी हैं। फ्रांस्वा लेटेक्सियर (उच्चारण की गफ़लत न हो इसलिए अंग्रेजी में François Letexier) दुनिया के सबसे बेहतरीन और हाई-प्रोफाइल फुटबॉल रेफरी में से एक हैं। वह मूल रूप से फ्रांस के रहने वाले हैं। खेल इतिहास और सांख्यिकी के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ (आईएफएफएचएस) उन्हें वर्ष 2024 का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष रेफरी घोषित कर चुका है। दोहराना जरूरी है कि फ्रांस्वा लेटेक्सियर फ्रांस के है,वही फ्रांस जिसे फाइनल में पेनाल्टी शूट में हराकर 2022 में अर्जेंटीना ने खिताब जीता था। घुटना मुड़ता तो पीठ की तरफ नहीं पेट की तरफ मुड़ता। इसके बाद भी यदि बंदे ने बेईमानी की है तो फिर तो अब फुटबॉल को रामई राक्खे !!

और अंत में

इस मुकाबले ने बता दिया मैसी गॉड,ईश्वर या खुदा नहीं है, ह्यूमन है। हाड़ मांस से बना बंदा है। पेनल्टी मिस करता है, हॉफ टाइम तक 2-0 से पिछड़ने के बाद फीनिक्स की तरह दोबारा झपटता है और फाइनली जीतता है। जीतने के बाद रोता है। पेनल्टी चूकने पर नहीं रोता,जीतने पर रोता है। उसके होते हुए भी अर्जेंटीना हार की कगार पर पहुंच सकती है और उसके रहते जीत भी सकती है।

विश्व नीति

अंशुमान

लेखक संसद टीवी से सम्बद्ध पत्रकार हैं।

वैश्विक सहयोग को आधार दे रही भारत की ऊर्जा नीति

विश्व अर्थव्यवस्था आज एक गहरे परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। पिछले तीन दशकों तक वैश्विक आर्थिक व्यवस्था पर विकसित देशों का दबदबा रहा, लेकिन अब यह संतुलन धीरे-धीरे उभरती अर्थव्यवस्थाओं की ओर खिसक रहा है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश अब केवल वैश्विक विकास में भागीदारी नहीं कर रहे, बल्कि उसकी दिशा और गति दोनों तय कर रहे हैं। इन देशों के विशाल और तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजार विकसित अर्थव्यवस्थाओं के उद्योगों को नई ऊर्जा दे रहे हैं। वहीं, इनकी बढ़ती विनिर्माण क्षमता वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक विविध और मजबूत बना रही है। स्थानीय उद्यमिता भी अब छोटे स्तर तक सीमित नहीं है बल्कि वह वित्त, लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य, डिजिटल सेवाओं और तकनीकी नवाचार जैसे क्षेत्रों में वैश्विक मानक स्थापित कर रही है।

वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं रह गया है कि क्या उभरती अर्थव्यवस्था वैश्विक विकास का नेतृत्व करेंगी, बल्कि यह प्रवृत्ति अब लगभग तय मानी जा सकती है। असली सवाल यह है कि क्या ये देश उस नेतृत्व को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने के लिए मजबूत आर्थिक, संस्थागत और सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा ढांचा तैयार कर रहे हैं। क्योंकि ऊर्जा किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की धड़कन है। उद्योगों का संचालन, कृषि का आधुनिकीकरण, डिजिटल अर्थव्यवस्था, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक वाहनों की वृद्धि इन सबकी नींव ऊर्जा पर ही टिकी है। आज ऊर्जा केवल बिजली उत्पादन या तेल आयात का विषय नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक आत्मनिर्भरता का मूल आधार बन चुकी है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA के अनुसार आने वाले वर्षों में वैश्विक बिजली मांग में होने वाली लगभग 80 प्रतिशत वृद्धि उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से आएगी। तेज़ औद्योगीकरण, शहरीकरण और डिजिटल विस्तार इस मांग को और बढ़ाएँगे। यह स्थिति विकास के बड़े अवसर भी देगी, लेकिन साथ ही ऊर्जा ढांचे पर भारी दबाव भी डालेगी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो देश अपनी ऊर्जा प्रणाली को समय रहते मजबूत नहीं करेंगे, वे आर्थिक विकास की इस दौड़ में पिछड़ सकते हैं।

इस वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण बनकर उभरती है क्योंकि भारत आज दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। पिछले एक दशक में देश ने डिजिटल परिवर्तन, आधारभूत संरचना के विस्तार, स्टार्टअप क्रांति और विनिर्माण क्षेत्र में जो गति हासिल की है, उसने भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक विकास के एक मजबूत इंजन के रूप में स्थापित किया है। आज दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी भारत को केवल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं, बल्कि उत्पादन, अनुसंधान और दीर्घकालिक निवेश के केंद्र के रूप में देख रही है। वैश्विक स्तर पर मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, पीएम गति शक्ति, PLI योजना और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जैसी पहलों ने भारत की औद्योगिक क्षमता को नई दशा के साथ नई दिशा भी दी है।

इन सभी उपलब्धियों की असली नींव एक मजबूत और भरोसेमंद ऊर्जा व्यवस्था ही है। अगर किसी देश में ऊर्जा की सप्लाई अस्थिर हो, कीमतें लगातार बदलती रहें या वह बहुत ज्यादा दूसरे देशों से आयात पर निर्भर हो, तो उसका सीधा असर उद्योगों, रोजगार और आर्थिक विकास पर पड़ता है। उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, निवेशकों का भरोसा कम हो जाता है और विकास की गति धीमी पड़ सकती है। इसी कारण आज ऊर्जा सुरक्षा सिर्फ एक तकनीकी या प्रशासनिक विषय नहीं रह गई है, बल्कि यह पूरे आर्थिक ढांचे की रीढ़ बन चुकी है।

भारत जैसे बड़े और तेजी से विकसित होते देश के लिए यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में इसमें और तेज़ी आने की संभावना है। अनुमान है कि वर्ष 2030 तक भारत में बिजली की मांग हर साल लगभग 6.4 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। यह वृद्धि केवल जनसंख्या बढ़ने के कारण नहीं होगी, बल्कि इसके पीछे कई बड़े कारण होंगे जैसे तेजी से फैलता हुआ औद्योगिक क्षेत्र, नए-नए डेटा सेंटरों का निर्माण, इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता उपयोग और डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार।

इसके अलावा शहरों का तेजी से बढ़ना, लोगों की जीवनशैली में बदलाव और तकनीक पर बढ़ती निर्भरता भी बिजली की मांग को और बढ़ाएगी। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में ऊर्जा की जरूरत सिर्फ घरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हर क्षेत्र चाहे वह उद्योग हो, परिवहन हो या सूचना प्रौद्योगिकी ऊर्जा पर और अधिक निर्भर होगा। इसका अर्थ साफ है कि भारत को केवल अधिक ऊर्जा नहीं, बल्कि ऐसी ऊर्जा व्यवस्था चाहिए जो निरंतर उपलब्ध हो, किफायती हो, विविध स्रोतों पर आधारित हो और संकट के समय भी स्थिर बनी रहे। इसी जरूरत ने भारत की ऊर्जा नीति को पिछले वर्षों में अधिक रणनीतिक और दीर्घकालिक बनाया है। विगत वर्षों में भारत ने अब यह समझ लिया है कि ऊर्जा सुरक्षा केवल आज की जरूरत नहीं, बल्कि भविष्य की प्रतिस्पर्धा तय करने वाला सबसे बड़ा कारक है।

हालाँकि भारत उन बड़े देशों में शामिल है जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर रहते हैं। इसलिए जब भी वैश्विक स्तर पर कोई संकट पैदा होता है, उसका असर भारत पर भी पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन हाल के वर्षों में जब ऐसे कई झटके आए, तब भारत ने जिस तरह से स्थिति को संभाला, वह उल्लेखनीय रहा है। देश ने न केवल तेजी से प्रतिक्रिया दी, बल्कि पूरे संतुलन और स्थिरता के साथ ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखा। इससे पूरी दुनिया में एक संदेश भी गया कि भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को सिर्फ कागज़ी नीति की तरह नहीं रखा, बल्कि इसे एक लंबे समय की राष्ट्रीय योजना के रूप में अपनाया है।

वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत में ईंधन की कमी नहीं हुई, घरेलू एलपीजी की सप्लाई भी नहीं रुकी और आम लोगों पर इसका असर बहुत सीमित रहा। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई विकसित देश भी ऐसे हालात में प्रभावित हो जाते हैं। यह सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे कई सालों की तैयारी और निवेश है। भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाए, रिफाइनिंग क्षमता को बढ़ाया, पाइपलाइन नेटवर्क को मजबूत किया, बंदरगाहों को आधुनिक बनाया और अलग-अलग देशों से ऊर्जा आयात करके एक ही देश पर निर्भरता कम की। इन सभी कोशिशों की वजह से भारत की ऊर्जा प्रणाली अब पहले से ज्यादा मजबूत और लचीली हो गई है, जिससे वह किसी भी संकट का सामना बेहतर तरीके से कर सकती है।

संकट के समय सरकार ने सिर्फ यह नहीं देखा कि सप्लाई बनी रहे, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखा कि आम लोगों पर बोझ कम पड़े। इसके लिए समय पर नियमों में बदलाव किए गए, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया गया, दूसरे देशों से वैकल्पिक आपूर्ति की व्यवस्था की गई और मांग को संतुलित रखने की कोशिश की गई। इससे यह समझ आता है कि ऊर्जा नीति सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह लोगों की रोज़मर्रा की जिंदगी और सामाजिक स्थिरता से भी जुड़ी होती है। भारत की ऊर्जा रणनीति का एक बड़ा हिस्सा विविधीकरण है, यानी अलग-अलग देशों से ऊर्जा लेना ताकि किसी एक देश पर निर्भरता न रहे। आज भारत 40 से ज्यादा देशों से ऊर्जा आयात करता है, जिससे किसी एक क्षेत्र में संकट आने पर पूरे देश की ऊर्जा व्यवस्था पर बड़ा असर नहीं पड़ता।

इसी रणनीति के तहत भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच ऊर्जा सहयोग भी बहुत मजबूत हुआ है। यह रिश्ता अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति, रणनीतिक भंडारण, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश और ऊर्जा परिवर्तन जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। भारत ने अपनी ऊर्जा कूटनीति को भी मजबूत किया है और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों जैसे पश्चिम एशिया, रूस, अमेरिका, अफ्रीका और मध्य एशिया के साथ संतुलित संबंध बनाए हैं। इसका फायदा यह हुआ कि भारत किसी एक देश या क्षेत्र पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहा और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा स्वतंत्रता मिली।

आज भारत केवल अपने देश तक सीमित नहीं है, बल्कि वह ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भी सहयोग कर रहा है। भारत ने पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान को ऊर्जा संकट के समय मदद भी दी है। इससे यह पता चलता है कि भारत केवल अपने विकास पर नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर भी ध्यान दे रहा है। कुल मिलाकर, भारत ने यह साबित किया है कि मजबूत ऊर्जा नीति सिर्फ देश की जरूरतों को पूरा करने का साधन नहीं है, बल्कि यह आर्थिक स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का भी एक महत्वपूर्ण आधार है।

आज स्थापना दिवस

चेतस सुखाड़िया

अभाविप : राष्ट्र निर्माण में छात्र शक्ति

भारत के राष्ट्रीय जीवन में विद्यार्थियों की भूमिका केवल शिक्षा प्राप्त करने तक सीमित नहीं रही है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर सामाजिक जागरण, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और राष्ट्रनिर्माण तक छात्रशक्ति ने समय-समय पर अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई है। इसी छात्र शक्ति को संगठित, संस्कारित और राष्ट्रोन्मुख बनाने के उद्देश्य से 9 जुलाई 1949 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की स्थापना हुई। आज 78वें स्थापना दिवस के अवसर पर यह केवल एक संगठन की वर्षगाँठ नहीं, बल्कि सात दशकों से अधिक समय से चल रहे एक ऐसे छात्र आंदोलन का उत्सव है, जिसने शिक्षा, समाज और राष्ट्र के बीच सशक्त संवाद स्थापित करने का प्रयास किया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के समक्ष केवल राजनीतिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने की चुनौती नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय चरित्र, शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक चेतना के पुनर्निर्माण का दायित्व भी था। ऐसे समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का ध्येय सामने रखते हुए यह विचार प्रस्तुत किया कि विद्यार्थी केवल 'भविष्य का नागरिक' नहीं, बल्कि 'आज का सक्रिय नागरिक' है। यही विचार आगे चलकर परिषद की कार्यशैली का आधार बना। 'ज्ञान, शील और एकता' का मूल मंत्र परिषद के व्यक्तित्व निर्माण के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है–ज्ञान से बौद्धिक विकास, शील से चरित्र निर्माण और एकता से राष्ट्र के प्रति समर्पण।

पिछले 78 वर्षों में परिषद ने छात्रहित के अनेक मुद्दों पर निरंतर कार्य किया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, समयबद्ध परिणाम, छात्रवृत्ति, छात्रावास, पुस्तकालयों का सुदृढ़ीकरण, शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहन, रोजगारोन्मुख शिक्षा तथा परिसरों में शैक्षणिक वातावरण को बेहतर बनाने जैसे विषय परिषद के प्रमुख अभियान रहे हैं। देश के अनेक विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की समस्याओं को लोकतांत्रिक माध्यमों से उठाने और उनके समाधान के लिए संवाद स्थापित करने में परिषद की सक्रिय भूमिका रही है।

अभाविप की पहचान केवल आंदोलनों से नहीं, बल्कि रचनात्मक कार्यों से भी जुड़ी है। संगठन ने समय-समय पर समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सेवा कार्यों के माध्यम से सिद्ध किया है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत एवं पुनर्वास, रक्तदान अभियान, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता अभियान, सामाजिक समरसता, ग्राम विकास, जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा तथा राष्ट्रीय एकता के कार्यक्रम परिषद की व्यापक सामाजिक दृष्टि को प्रतिबिंबित करते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान भी परिषद के कार्यकर्ताओं ने देशभर में राहत कार्यों में उल्लेखनीय भागीदारी निभाई।

अभाविप की कार्यपद्धति का एक विशिष्ट पक्ष उसके विविध आयाम हैं, जिनके माध्यम से संगठन विद्यार्थियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास का प्रयास करता है। स्टूडेंट्स फॉर डेवलपमेंट (SFD) पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन, जैव विविधता, सतत विकास और जनजागरूकता के माध्यम से युवाओं को प्रकृति के प्रति उत्तरदायी बनाता है। वहीं स्टूडेंट्स फॉर सेवा (SFS) समाज के वंचित वर्गों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार और सेवा गतिविधियों को पहुँचाकर छात्रशक्ति को सामाजिक दायित्वों से जोड़ने का कार्य करता है। इसी प्रकार 'खेलो भारत' अभियान के माध्यम से परिषद महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करते हुए स्वस्थ, अनुशासित और ऊर्जावान युवा पीढ़ी के निर्माण का प्रयास कर रही है। वहीं 'राष्ट्रीय कला मंच' भारतीय कला, संस्कृति, साहित्य, लोक परंपराओं और सृजनात्मक अभिव्यक्तियों को मंच प्रदान कर विद्यार्थियों में सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय गौरव का भाव विकसित करता है।

संगठन का विश्वास है कि महिला सशक्तिकरण के बिना राष्ट्र का समग्र विकास संभव नहीं है। इसी दृष्टि से छात्राओं के नेतृत्व विकास, सुरक्षा, स्वाभिमान, उच्च शिक्षा में समान अवसर तथा व्यक्तित्व निर्माण के लिए परिषद निरंतर कार्य कर रही है। 'मिशन साहसी' जैसे अभियानों के माध्यम से लाखों छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देकर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया गया है। छात्रावासों की सुविधाएँ, परिसर सुरक्षा, महिला स्वास्थ्य, शिक्षा में समान अवसर तथा नेतृत्व निर्माण जैसे विषयों पर परिषद लगातार रचनात्मक पहल और लोकतांत्रिक संवाद करती रही है। आज एबीवीपी के विभिन्न स्तरों पर बड़ी संख्या में छात्राएँ नेतृत्वकारी भूमिका निभा रही हैं, जो संगठन की समावेशी कार्यसंस्कृति और महिला नेतृत्व के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

आज भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देशों में अग्रणी है। यदि इस युवा शक्ति को सही दिशा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल, नवाचार और राष्ट्रीय दृष्टि प्राप्त हो, तो भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को अपेक्षाकृत कम समय में प्राप्त कर सकता है। इस संदर्भ में छात्र संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। अभाविप ने युवाओं में नेतृत्व क्षमता, सामाजिक उत्तरदायित्व, संगठन कौशल और राष्ट्रभाव विकसित करने के लिए अनेक प्रशिक्षण, अध्ययन, संवाद और नेतृत्व विकास कार्यक्रम संचालित किए हैं।

वर्तमान समय में शिक्षा जगत तीव्र परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल शिक्षा, स्टार्टअप संस्कृति, अनुसंधान, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे विषय नई पीढ़ी के सामने अवसर और चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे समय में केवल तकनीकी दक्षता पर्याप्त नहीं है। आवश्यक है कि विद्यार्थियों में नैतिकता, संवेदनशीलता, लोकतांत्रिक आचरण और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व भी विकसित हो। यही वह संतुलन है जिसकी आवश्यकता आज के भारत को है।

परिषद ने भारतीय ज्ञान परंपरा, मातृभाषा में शिक्षा, अनुसंधान संस्कृति, नवाचार तथा आत्मनिर्भर भारत जैसे विषयों पर भी निरंतर विमर्श को आगे बढ़ाया है। साथ ही पूर्वोत्तर भारत, सीमांत क्षेत्रों और जनजातीय अंचलों के विद्यार्थियों को मुख्यधारा से जोड़ने तथा 'एक जन - एक राष्ट्र - एक संस्कृति' की भावना को मजबूत करने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य केवल संगठन विस्तार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकात्मता को सुदृढ़ करना भी है।

यह भी उल्लेखनीय है कि परिषद ने अनेक ऐसे कार्यकर्ता तैयार किए जिन्होंने आगे चलकर शिक्षा, प्रशासन, विज्ञान, न्यायपालिका, उद्योग, सामाजिक जीवन और सार्वजनिक जीवन के विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया। इससे स्पष्ट होता है कि छात्र जीवन में प्राप्त संगठनात्मक संस्कार व्यक्ति के दीर्घकालीन व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

78वाँ स्थापना दिवस केवल उपलब्धियों का स्मरण नहीं, बल्कि भविष्य के प्रति नए संकल्प का अवसर भी है। भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में शिक्षित, संस्कारित और उत्तरदायी युवा शक्ति सबसे बड़ी पूँजी सिद्ध होगी। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के परिसर केवल डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान न बनें, बल्कि चरित्र, नेतृत्व, शोध, नवाचार और सामाजिक उत्तरदायित्व के केंद्र बनें–यह समय की आवश्यकता है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि छात्र राजनीति केवल चुनावों तक सीमित न रहे, बल्कि शिक्षा सुधार, सामाजिक संवेदनशीलता, पर्यावरण संरक्षण, संवैधानिक मूल्यों, नवाचार और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर भी सक्रिय भूमिका निभाए। जब विद्यार्थी अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का भी समान रूप से निर्वहन करेगा, तभी शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण होगा।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 78वें स्थापना दिवस पर हम उन सभी ज्ञात-अज्ञात कार्यकर्ताओं को नमन करते हैं जिन्होंने अपने परिश्रम, त्याग और समर्पण से इस संगठन को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया। अभाविप की यह प्रतिबद्धता है कि राष्ट्रहित, छात्रहित और समाजहित के अपने संकल्प को और अधिक प्रभावी रूप से आगे बढ़ाते हुए विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण में छात्र शक्ति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी।

खातों में नहीं आयेगी राशि, आदेश अभी तक अप्राप्त फिर बदले नियम, अब बच्चों को मिलेगी रेडीमेड ड्रेस

एस. द्विवेदी, बैतूल। जिले के शासकीय स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी। 15 जून से शुरू हुए नये शैक्षणिक सत्र को करीब एक पखवाड़े से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन कक्षा पहली से आठवीं तक के करीब 1 लाख 18 हजार छात्र अब भी गणवेश का इंतजार कर रहे हैं। शासन की ओर से अब तक छात्रों के बैंक खातों में न तो गणवेश खरीदने के लिए 600 रुपए की राशि पहुंची है और न ही स्कूलों में नई ड्रेस वितरित की गई है। इसका परिणाम यह है कि कई बच्चे पुराने और फटे-पुराने गणवेश में स्कूल पहुंच रहे हैं, जबकि जिनके पास गणवेश नहीं है, वे सामान्य कपड़ों में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। जानकारी के अनुसार, शासन इस बार गणवेश वितरण की व्यवस्था में फिर बदलाव करने जा रहा है। पहले छात्रों के खातों में राशि भेजने की व्यवस्था थी, लेकिन अब तैयार सिली हुई दो जोड़ी गणवेश विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने की योजना पर काम चल रहा है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पर भी काम चल रहा है। यही कारण है कि न राशि जारी हो सकी है और न ही गणवेश का वितरण शुरू हो पाया है। बता दे कि वैसे भी हर साल सत्र

के चार से पांच महीने बाद ही स्कूल ड्रेस की प्रक्रिया शुरू होती है। जिले में पिछले शैक्षणिक सत्र में बच्चों को ड्रेस उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इन विद्यार्थियों के बैंक खातों में स्कूल ड्रेस की राशि के रूप में भुगतान किया गया।

तीन साल बाद फिर नियमों में बदलाव - बताया जा रहा है कि विद्यार्थियों को सरकार की ओर से मिलने वाली स्कूल ड्रेस को लेकर तीन साल बाद फिर नियमों में बदलाव किया जा रहा है। अब कक्षा एक से 8 तक के छात्रों के बैंक खातों में स्कूल ड्रेस के लिए आने वाली 600 रुपये की नकद राशि की जगह इस बार सरकार शासकीय स्कूल के विद्यार्थियों को सिली-सिलाई ड्रेस देगी। जिसके लिए पोर्टल पर डाटा अपडेट किया जा चुका है। इस बदलाव को शिक्षा व्यवस्था में एक बड़े यू-टर्न के तौर पर देखा जा रहा है। नियमों में बदलाव को लेकर विभागीय अधिकारी चिंतित नजर आ रहे है, क्योंकि स्कूल शुरू होने के साथ ही विद्यार्थियों की स्कूल ड्रेस को लेकर शासन स्तर से कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।

कई बार बदली जा चुकी है गणवेश वितरण की व्यवस्था

गौरतलब है कि गणवेश वितरण की व्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में कई बार बदली जा चुकी है। तीन वर्ष पहले स्व-सहायता समूहों को गणवेश सिलने का जिम्मा दिया गया था, ताकि समूहों को रोजगार मिल सके, लेकिन सिलाई और वितरण में हुई देरी के कारण पूरे सत्र में गणवेश बांटने की प्रक्रिया चलती रही और शासन को आलोचना का सामना करना पड़ा। यह व्यवस्था समाप्त कर छात्रों के खातों में सीधे राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। इससे पहले विकासखंड स्तर पर गणवेश खरीदी के लिए मेले भी लगाए जाते थे, जहां से स्कूलों के माध्यम से गणवेश खरीदे जाते थे। गुणवत्ता संबंधी शिकायतें सामने आने के बाद वह व्यवस्था भी बंद कर दी गई। अब एक बार फिर नई प्रणाली लागू करने की तैयारी ने पुरानी समस्या को दोहरा दिया है।

बार-बार व्यवस्था बदलने से बच्चे हो रहे परेशान

बार-बार व्यवस्था बदलने के कारण हर साल शुरुआती सत्र में छात्र ही सबसे अधिक परेशान होते हैं। शिक्षा विभाग और शासन के बीच नीति तय होने तक बच्चों को बिना गणवेश या पुराने कपड़ों में स्कूल जाना पड़ रहा है। सवाल यह है कि जब हर वर्ष सत्र शुरू होने की तारीख तय रहती है, तो गणवेश जैसी बुनियादी व्यवस्था समय पर सुनिश्चित क्यों नहीं की जा सकी। मालूम हो कि शासकीय स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा 3 साल से ड्रेस के लिए 600 रुपए डीबीटी माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी जा के रही थी। लेकिन इस साल प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस के लिए राशि नहीं बल्कि सिली-सिलाई ड्रेस का वितरण किया जायेगा।

10 साल में बदले मॉडल

जानकार बताते है कि 2016-17 से 2018-19 की अवधि में स्कूल ड्रेस वितरण की जिम्मेदारी शाला प्रबंधन समितियों (एसएमसी) को दी गई थी, जो स्थानीय टेलर्स से स्कूल ड्रेस सिलवाकर वितरित करती थीं। फिर 2019-20 में सरकार ने महिला स्व-सहायता समूहों को यूनिफॉर्म का काम दिया। 2020-21 और 2021-22 (कोविड काल) में स्कूल ड्रेस के स्थान पर सीधे विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से नकद राशि दी गई। 2022-23 में फिर से स्व-सहायता समूहों को यूनिफॉर्म का काम दिया। इसके बाद विद्यार्थियों के खाते में राशि भुगतान करने की व्यवस्था बनाई गई। अब फिर से विद्यार्थियों को सिली-सिलाई स्कूल ड्रेस दिये जाने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है।

इनका कहना है -

गणवेश के लिए हमनें सभी विद्यार्थियों का भौतिक सत्यापन कर लिया है। बैंक खातों की जानकारी भी अपडेट कर ली हैं। शासन स्तर से जैसे निर्देश प्राप्त होंगे, वैसे आगे की प्रक्रिया होगी। जहां तक गणवेश वितरण प्रक्रिया में बदलाव की बात हैं तो हमें आदेश नहीं मिले हैं। शायद शासन स्तर पर प्रक्रिया चल रही होगी।

- सुधीर कुमार साकेत, डीपीसी, बैतूल

ताप्ती जन्मोत्सव की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित

पवित्र नगरी मुलताई को बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करें

बैतूल। ताप्ती जन्मोत्सव की तैयारी को लेकर जनपद पंचायत मुलताई में बुधवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुलताई विधायक श्री चंद्रशेखर देशमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजा पवार, नगर पालिका अध्यक्ष नीतू परमार, वर्षा गढ़ेकर, जनपद अध्यक्ष नानीबाई डहारे, कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे, एसडीएम राजीव कहार सहित ताप्ती मंदिर ट्रस्ट के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पवित्र ताप्ती नगरी मुलताई को बड़े धार्मिक एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अभी से व्यवस्थित और दूरदर्शी प्लानिंग तैयार की जाए। बैठक में ताप्ती उद्गम स्थल के समग्र विकास, श्रद्धालुओं की सुविधाओं के विस्तार तथा पर्यटन की दृष्टि से आवश्यक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मुलताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख ने कहा कि ताप्ती उद्गम स्थल के विकास की योजना इस प्रकार तैयार की जाए कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सभी आवश्यक सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कुंड के आसपास बेहतर लाइटिंग व्यवस्था, कवर्ड नालियों का निर्माण तथा श्रद्धालुओं के बैठने के लिए पर्याप्त संख्या में बेंच लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्य वेलकम गेट को आकर्षक डिजाइन के साथ विकसित कर आधुनिक लाइटिंग की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार ने घाट विकास, पेयजल व्यवस्था, स्मार्ट शौचालय, कंट्रोल रूम सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं के लिए विस्तृत प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ सोनवणे ने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अभी से समग्र विकास योजना तैयार की जाए। उन्होंने श्रद्धालुओं के ठहरने की सुविधा के लिए भक्त निवास निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने ने एसडीएम एवं नगर पालिका सीएमओ को ताप्ती मंदिर के आसपास स्थित जर्जर भवनों का सर्वे कर उन्हें चिन्हित करने के निर्देश दिए। साथ ही छोटे तालाब को स्टेप-सेटिंग सीढ़ीनुमा घाट के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना तैयार करने को कहा। उन्होंने नगर पालिका सीएमओ एवं राजस्व अधिकारियों को मंदिर परिक्रमा परिसर सहित दो किलोमीटर के दायरे में स्थित वैध एवं अवैध भूमि का अद्यतन रिकॉर्ड तैयार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की बेहतर योजना और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए भूमि संबंधी सभी जानकारी व्यवस्थित रूप से उपलब्ध रहनी चाहिए।

श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए कलेक्टर ने एसडीएम को मंदिर परिसर में भीड़ प्रबंधन के लिए व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने पूरे परिसर के लिए एंट्री एवं एग्जिट प्लान तैयार करने, परिक्रमा मार्ग पर माइक एवं साउंड सिस्टम लगाने तथा व्यापक स्तर पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी व्यवस्था किसी भी संवेदनशील स्थिति से निपटने तथा परिसर में बिछड़ने वाले बच्चों की तलाश जैसे कार्यों में भी उपयोगी होगी। उन्होंने मंदिर परिसर में सभी दुकानों को व्यवस्थित रूप से संचालित कराने के निर्देश देते हुए प्रवाह क्षेत्र में किए गए अतिक्रमणों को चिन्हित कर हटाने की कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को क्षेत्र के सभी नालों की मैपिंग कराने के निर्देश भी दिए।

चित्रकला और साइबर टेस्ट के जरिए बच्चों ने दी डिजिटल सुरक्षा की सीख

साइबर अपराधों से बचाव का संदेश लेकर आगे आए श्री विनायकम स्कूल के विद्यार्थी, सेफ क्लिक-2.0 के समापन में विद्यार्थियों ने बिखेरे प्रतिभा के रंग

बैतूल। साइबर सुरक्षा के प्रति बच्चों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित सेफ क्लिक-2.0 अभियान के समापन समारोह में श्री विनायकम स्कूल के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी रचनात्मकता, जागरूकता और डिजिटल सुरक्षा के प्रति समझ का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों की प्रस्तुति ने कार्यक्रम में मौजूद पुलिस अधिकारियों और अतिथियों का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने साइबर सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता विषय पर आकर्षक चित्रकला और ड्राइंग तैयार कर सुरक्षित डिजिटल जीवन का संदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने साइबर जागरूकता

परीक्षण (अवेयरनेस टेस्ट) में भी भाग लिया, जिसमें साइबर अपराधों से बचाव, सुरक्षित इंटरनेट उपयोग और डिजिटल जिम्मेदारियों से जुड़े विषयों पर अपने ज्ञान को परखा और उसे और अधिक विकसित किया। समापन समारोह में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपुसे, डीएसपी (महिला सेल) दुर्गेश आरमो, एसडीओपी बैतूल अन्नपूर्णा सिरसाम, आरआई दिनेश मर्सकोले, एसआई अश्विनी चौधरी, एसआई नवीन सोनकर सहित संपूर्ण साइबर टीम मौजूद रही। अधिकारियों ने विद्यार्थियों की रचनात्मक सोच, सक्रिय सहभागिता और साइबर सुरक्षा के प्रति उनकी रुचि की सराहना करते हुए उन्हें डिजिटल दुनिया में सतर्क रहने तथा साइबर सुरक्षा संबंधी जागरूकता को अपने परिवार, मित्रों और समाज तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। श्री विनायकम स्कूल के डायरेक्टर संजय राठौर ने विद्यार्थियों की उल्लेखनीय सहभागिता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि साइबर सेल द्वारा किए जा रहे जागरूकता प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने बताया कि विद्यालय में भी समय-समय पर साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें साइबर सेल की सक्रिय सहभागिता रहती है। ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करने के साथ उन्हें जिम्मेदार, जागरूक और सुरक्षित डिजिटल नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं।

भूतपूर्व सैनिकों की मासिक बैठक आज

बैतूल। जिले के भूतपूर्व सैनिकों और शहीदों की पत्नियों की मासिक बैठक आज गुरुवार 9 जुलाई को जिला सैनिक कल्याण कार्यालय बैतूल में प्रातः 11 बजे से आयोजित की जाएगी। सेवानिवृत्त कैप्टन आईएन सुमीत सिंह, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी बैतूल ने जिले के सभी भूतपूर्व सैनिकों एवं शहीदों की पत्नियों से इस बैठक में निर्धारित समय पर उपस्थित होने का अनुरोध किया है। बैठक में भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित समस्याओं, कल्याणकारी योजनाओं और आवश्यक विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

सरपंच संघ ने जनपद अध्यक्ष के नेतृत्व में अनुविभागीय अधिकारी को मूंग की शत-प्रतिशत खरीदी के संबंध में ज्ञापन सौंपा

सोहागपुर। जनपद पंचायत कार्यालय परिसर से सरपंच संघ ने किसानों की समस्यायों को लेकर रेली निकाली। रैली जनपद पंचायत कार्यालय न्यायालय चौराहा, पलकमती नदी पुल, मुख्य बाजार से होकर नारेबाजी करते अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय पहुंची। रैली में किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए गए।

जनपद पंचायत अध्यक्ष जालमसिंह पटेल के नेतृत्व में अनुविभागीय अधिकारी डॉ बबीता राठौर को ज्ञापन सौंपा। इसके पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष जालमसिंह पटेल ने ज्ञापन का वाचन किया। इस ज्ञापन में मूंग खरीदी को 100 प्रतिशत खरीदी ,मूंग खरीद केंद्र को बढ़ाने के अलावा किसानों को कम से कम 10 घंटे बिजली प्रदाय कराने के साथ किसानों को डी.ए.पी. टोकन की व्यवस्था को विधिवत करने आदि की प्रमुख मांगे थी। ज्ञापन में आगे कहा गया कि सरपंच संगठन सोहागपुर की समस्त 62 ग्राम पंचायतों के सरपंचों की ओर से आपसे सर्वसम्मति से निवेदन करते है ।कि हमारी समस्या को माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराजसिंह जी चौहान एवं मुख्यमंत्री श्री डॉ. मोहन यादव जी तक पहुंचाने का कष्ट करें। हम सभी सरपंच साथी जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से आते है इस समय ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या किसानो की बनी हुई है जो कि उनकी दशा एवं व्यथा हम जनप्रतिनिधियों से देखी नहीं जा रही है। क्योंकि हम खुद किसान के बेटे और खुद किसान है। केन्द्र एवं राज्य बैठी तक किसानों की आवाज पहुंचाने का कार्य हम सभी जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है । वहीं हमें हमेशा किसानो एवं जनता के बीच में रहना पड़ता है ।इसलिये आपसे निवेदन है कि हमारी समस्या का समाधान जल्द से जल्द करवाया जाए। उक्त सभी मांगो को पूरा किया जाए। यदि उक्त मांगे समय से पूरी नहीं की जाती है तो हमे मजबूरन विरोध प्रदर्शन करने को बाध्य होना पड़ेगा। इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष जालमसिंह पटेल,जनपद पंचायत उपाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह पटेल, सरपंच संघ अध्यक्ष सुरेंद्र पटेल,माछा सरपंच सुधीर ठाकुर, बलराम पटेल प्रेम शंकर मेहरा ,मीना बाई, चंदन सिंह ,श्यामा बाई पुरनलाल ,सुनीता आदि उपस्थित थे।

पानी नहीं मिलने पर नगरपालिका पहुंचे पार्षद

बैतूल। जिला मुख्यालय के कई वार्डों में पिछले पांच से छह दिनों से पेयजल संकट बना हुआ है। कई इलाकों में नलों से पानी नहीं पहुंचा, जबकि जहां जलापूर्ति हुई वहां गंदा पानी आने की शिकायतें सामने आईं। समस्या से परेशान रहवासियों और पार्षदों ने नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) नवनीत पांडे से तत्काल समाधान की मांग की। पार्षदों ने बताया कि अनियमित जलापूर्ति के कारण लोगों को दैनिक जरूरतों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, दूषित पानी की आपूर्ति से स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बढ़ गए हैं। उन्होंने सभी प्रभावित वार्डों में नियमित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के साथ पाइपलाइन की जांच कराने की मांग की। सीएमओ नवनीत पांडे ने बताया कि कॉलेज चौक क्षेत्र में मुख्य पेयजल पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण जलापूर्ति प्रभावित हुई थी। पाइपलाइन की मरम्मत में करीब 48 घंटे का समय लगा, जिससे कई वार्डों में पानी की सप्लाई बाधित रही। उन्होंने कहा कि तकनीकी खराबी को दूर कर लिया गया है और व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से सामान्य किया जा रहा है। सीएमओ ने बताया कि बुधवार शाम से प्रभावित वार्डों में दोबारा नियमित जलापूर्ति शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि किसी क्षेत्र से गंदे पानी की शिकायत मिलती है तो उसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका ने नागरिकों से कुछ समय तक सहयोग की अपील करते हुए जल्द स्थिति सामान्य होने का भरोसा दिलाया।

कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने औद्योगिक क्षेत्र मोही का किया निरीक्षण

बैतूल। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने बुधवार को औद्योगिक क्षेत्र मोही का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं एवं अधोसंरचनात्मक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, जल निकासी, विद्युत, पेयजल, साफ-सफाई तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को औद्योगिक क्षेत्र की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने तथा उद्योगों स्थापना में आने वाली समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास को गति देने के लिए आवश्यक अधोसंरचना एवं सुविधाएं गुणवत्तापूर्ण और सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जाए, जिससे उद्यमियों को बेहतर वातावरण मिल सके। इस अवसर पर मुलताई एसडीएम राजीव कहार, जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र महाप्रबंधक धीरज मंडलेकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रदेश भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ अध्यक्ष खंडेलवाल के प्रथम नगरागमन पर भव्य स्वागत

सोहागपुर। प्रदेश भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्री धीरज जी खण्डेलवाल के प्रथम नगर आगमन के अवसर पर सी फोर सिटी माल में आयोजित स्वागत एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अतिथियों को व्यापारियों ने पगड़ी पहनाकर पुष्पमालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर समाजसेवी कन्नू लाल अग्रवाल, रमेश चंद्र खंडेलवाल,अभय खंडेलवाल,

राजू अग्रवाल सेमरी हरचंद,मोन्टू अग्रवाल, नारायण छाबड़िया,गोलू अग्रवाल, निपुण खंडेलवाल,यश खंडेलवाल, विजय छाबड़िया नन्नू भैया,गौरव माहेश्वरी,राजा अग्रवाल,प्रतिपाल सिंह खनूजा, भाजपा ब्लाक अध्यक्ष अश्विनी सरोज,युवा भाजपा

नेता अभिनव पालीवाल, माधव भावसार, मनोज अग्रवाल, व्यापारी संघ अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, आकाश रघुवंशी साहू जी सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह ने स्वागत भाषण में प्रदेश भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्री खंडेलवाल की प्रशंसा करते उनके कार्यों का सारगर्भित उद्बोधन दिया। इसी क्रम में प्रदेश भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्री धीरज खंडेलवाल के प्रथम नगरागमनन पर क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह ने मां नर्मदा का स्मृति चिन्ह भेंट किया । इसके पूर्व व्यापारियों ने अतिथियों का शाल-श्रीफल से भी स्वागत करके अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में नगर के समस्त व्यापारी बंधु एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसके पूर्व ही फोर सिटी माल के प्रवेशद्वार पर मोंटू अग्रवाल की अगुवाई में श्री धीरज खंडेलवाल एवं क्षेत्रीय विधायक विजयपालसिंह का पुष्प मालाओं से स्वागत सत्कार करके स्वागत कक्ष में प्रवेश कराया गया।

कार्यालय नगर पालिका परिषद बैतूल (म.प्र.)

क्रमांक/लो.नि.शा./ई./2945 to 2948 // ई- टेन्डर आमंत्रण सूचना // बैतूल दिनांक 06/07/2026

(प्रथम निविदा आमंत्रण सूचना)

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in/nicgep/app पर देखा जा सकता है।

क्र.	ऑन लाईन निविदा क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2026_UAD_519477_1	CONSTRUCTION OF HUME PIPE CHEMBAR DRAIN GOULI MOHALLA NEAR HEMANT YADAV HOUSE IN MOTI WARD BETUL	1- 30 Days 2- 220605/-	1- 2000/- 2-2200/-	22/07/2026
2	2026_UAD_519478_1	CONSTRUCTION OF CC ROAD DINESH DIGARSE HOUSE TO MISHRA JI HOUSE IN SHASHTRI WARD BETUL	1-30 Days 2-162630/-	1- 1000/- 2- 3300/-	22/07/2026
3	2026_UAD_519479_1	CONSTRUCTION OF CC ROAD MAGARDE JI HOUSE TO SURYWANSHI IN INDIRA WARD BETUL	1- 45 Days 2- 595636/-	1-2000/- 2-6000/-	22/07/2026
4	2026_UAD_519480_1	CONSTRUCTION OF HUME PIPE CHEMBAR DRAIN IN BHGATSINGH WARD BETUL	1- 55 Days 2- 698753/-	1-2000/- 2-7000/-	22/07/2026

नोट :- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in/nicgep/app की वेबसाईड पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नही किया जावेगा।

(नवनीत पाण्डेय) सीएमओ, नगर पालिका परिषदे, बैतूल

संक्षिप्त समाचार

अवैध शराब के विरुद्ध आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में अवैध शराब के निर्माण, विक्रय, परिवहन एवं संग्रहण के विरुद्ध आबकारी विभाग द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जिला आबकारी अधिकारी डॉ. राजीव प्रसाद द्विवेदी के मार्गदर्शन में वृत्त पिपरिया शहर अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर आकस्मिक दबिश देकर अवैध मदिरा के विरुद्ध सघन अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान अंबेडकर वार्ड, कुचबंदिया मोहल्ला, हाथवास, ग्राम राईखेड़ी एवं रिछेड़ा में दबिश देकर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1) के तहत कुल 8 प्रकरण कायम किए गए। इस दौरान 680 किलोग्राम महुआ लाहन एवं 19 लीटर हाथ भट्टी निर्मित अवैध मदिरा जब्त की गई। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग 71 हजार 800 रुपये आंकी गई है। यह कार्रवाई वृत्त प्रभारी श्री हितेश कुमार बिशोरिया के नेतृत्व में की गई, जिसमें आबकारी आरक्षक श्री गणपति बोबड़े का सराहनीय योगदान रहा। आबकारी विभाग ने बताया कि जिले में अवैध मदिरा के निर्माण एवं कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं तथा ऐसे मामलों में निरंतर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देश पर शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार शहर में यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने एवं सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण मुक्त करने के उद्देश्य से विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, तहसीलदार नर्मदापुरम शहर श्रीमती सरिता मालवीय एवं नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) श्री वैभव देशमुख के नेतृत्व में शहर के प्रमुख मार्गों, कमिश्नर कार्यालय के सामने तथा जिला जेल के सामने अवैध रूप से सड़क एवं सार्वजनिक स्थानों पर फल एवं सब्जी की दुकानें लगाकर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। अभियान के दौरान हाथ ठेले एवं अन्य सामान की जप्ती की कार्रवाई की गई तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर नियमानुसार जुर्माना भी लगाया गया। अधिकारियों ने सभी दुकानदारों को समझाइश देते हुए निर्देश दिए कि वे भविष्य में केवल नगर पालिका द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही अपनी दुकानें एवं हाथ ठेले लगाएं। साथ ही चेतावनी दी गई कि सार्वजनिक मार्गों पर पुनः अतिक्रमण पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान राजस्व विभाग, नगर पालिका के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा आवश्यक पुलिस बल मौजूद रहा।

कलेक्टर विश्वकर्मा की अध्यक्षता में मेरा युवा भारत अंतर्गत जिला सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न

रायसेन (निप्र)। मेरा युवा भारत अंतर्गत जिला सलाहकार समिति की बैठक कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उन्होंने जिले में मेरा युवा भारत पोर्टल पर 15 से 29 आयु वर्ग के अधिक से अधिक युवाओं का पंजीयन, विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय तथा वार्षिक कार्ययोजना अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा कर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों से अपने-अपने विभाग, शैक्षणिक संस्थानों, ग्राम पंचायतों, अशासकीय संगठनों तथा अन्य माध्यमों से अधिक से अधिक युवाओं का पोर्टल पर पंजीयन सुनिश्चित कराने का आग्रह किया गया। साथ ही प्रत्येक विभाग एवं संस्था से My Bharat गतिविधियों के प्रभावी संचालन हेतु समन्वय स्थापित करने पर बल दिया गया। इसी प्रकार वार्षिक कार्ययोजना अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले विभिन्न अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रमों के संचालन हेतु विभिन्न विभागों की भूमिका एवं समन्वय पर चर्चा की गई। बैठक में युवाओं को प्रशासनिक, न्यायिक, औद्योगिक, तकनीकी, सामाजिक एवं विकासात्मक संस्थाओं से जोड़ने के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर भी चर्चा की गई।

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा की अध्यक्षता में टीएल बैठक सम्पन्न

समय सीमा वाले प्रकरणों में प्राथमिकता करें कार्यवाहीं: कलेक्टर विश्वकर्मा

रायसेन (निप्र)। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सोमवार को आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा समय सीमा वाले प्रकरणों, सीएम हेल्पलाईन, मूंग उपार्जन सहित योजनाओं तथा निर्माण कार्यों की विभागवार विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के प्रारंभ में उन्होंने राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान तहसीलवार नामांतरण प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करते हुए नामांतरण प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्रकरण समयावधि के पहले ही निराकृत किए जाएं।

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम अधिनियम के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि 54 प्रकरण समयावधि से बाहर होने वाले हैं, जिन्हें शीघ्रता से निराकरण कराएं। उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदार और अधिकारियों को निर्देशित किया कि समयावधि वाले सभी प्रकरणों को

गंभीरता से लें अंतिम निराकरण कराएं। सीएम हेल्पलाईन शिकायतों की विभागवार समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने निर्देश दिए कि शिकायतों का प्राथमिकता से अंतिम निराकरण कराएं।

कोई भी शिकायत अधिक समय तक लंबित ना रहे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कोई भी शिकायत नॉन अटेन्डनेट ना रहे और ना ही निम्न गुणवत्ता से बंद हो। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने सभी एसडीएम को निर्देशित कि कि धारणाधिकार के प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही करते हुए उन्हें जिला स्तर पर भिजवाएं।

इसी प्रकार फार्मर रजिस्ट्री में अभी भी बहुत काम होना है, एसडीएम नियमित रूप से प्रतिदिन मॉनीटरिंग कर कार्य में तेजी लाएं। मूंग उपार्जन कार्य की समीक्षा करते हुए उन्होंने केन्द्रों पर समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने और नीति अनुरूप उपार्जन कार्य पूर्ण कराने के लिए कहा। इसके अतिरिक्त जिले में खाद की उपलब्धता तथा वितरण की जानकारी लेते हुए व्यवस्थित रूप से खाद वितरण हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया। संबल योजना में पंजीयन के लंबित आवेदनों की समीक्षा कर सीएमओ तथा जनपद सीईओ को शीघ्रता से कार्यवाही करने के लिए कहा गया। सभी जनपद सीईओ को वीबी-जी रामजी योजना का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के लिए भी निर्देश दिए गए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, समग्र सीडिंग, एक बगिया मां के नाम परियोजना, निर्माणाधीन पंचायत भवनों की कार्य प्रगति सहित ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अन्य विकास कार्यों की भी समीक्षा कर जनपद सीईओ को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबल 2.0 योजना के आवेदनों, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में श्रमिकों का पंजीयन तथा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का अधिक से अधिक पथ विक्रेताओं का लाभ दिए जाने के भी निर्देश दिए।

कलेक्टर विश्वकर्मा ने विभिन्न ग्रामों का भ्रमण कर योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यो का लिया जायजा

रायसेन (निप्र)। शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन और निर्माण कार्यों की वस्तुस्थिति जानने कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा सोमवार को जिले में विभिन्न ग्रामों का भ्रमण कर आंगनवाड़ी केन्द्र, शासकीय स्कूल तथा निर्माण कार्यो का निरीक्षण किया गया। उन्होंने ग्राम किशनपुर में आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्र का निरीक्षण कर आंगनवाड़ी केन्द्र में दर्ज बच्चों तथा नियमित आने वाले बच्चों की संख्या, शैक्षणिक गतिविधियों, पोषण आहार वितरण आदि की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा अधिकारियों से जानकारी ली। साथ ही बच्चों से भी संवाद कर आंगनवाड़ी में खेल गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि बच्चों को रचनात्मक तरीके से शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ा जाए। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा द्वारा सिलवानी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत छीतापार में नवनिर्मित अटल ग्राम सेवा सदन (पंचायत भवन) का निरीक्षण किया गया। उन्होंने ग्राम पंचायत में शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, विकास कार्यों की जानकारी ली तथा उपस्थित अधिकारियों को योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर सभी पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। इसके उपरांत कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने बम्होरी में पीएमश्री शासकीय उ.मा.विद्यालय तथा शासकीय कन्या उ.मा.विद्यालय का निरीक्षण किया।

वर्षा ऋतु में सुरक्षित पेयजल हेतु किया जा रहा जल स्त्रोतों का क्लोरीनेशन

सीहोर (निप्र)। वर्षा ऋतु के दौरान जलजनित बीमारियों रोकथाम के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल स्त्रोतों का क्लोरीनेशन किया जा रहा है। अभियान के तहत हैंडपंपों, नल-जल योजनाओं तथा अन्य पेयजल स्त्रोतों में क्लोरीन डाला जा रहा है, ताकि नागरिकों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। विभाग द्वारा पेयजल की गुणवत्ता पर लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। इसके लिए विभिन्न स्थानों से जल के नमूने एकत्र कर पेयजल परीक्षण किट के माध्यम से उनकी जांच की जा रही है। परीक्षण के आधार पर आवश्यकतानुसार क्लोरीनेशन सहित अन्य सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे दूषित पानी के कारण होने वाली बीमारियों की रोकथाम सुनिश्चित की जा सके। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे केवल स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल का ही उपयोग करें। यदि किसी क्षेत्र में पेयजल की गुणवत्ता या जल स्त्रोत से संबंधित कोई समस्या दिखाई दे, तो उसकी सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। जिलेभर में वर्षाकाल के दौरान पेयजल स्त्रोतों में क्लोरीनेशन एवं जल गुणवत्ता परीक्षण का कार्य निरंतर जारी है।

भूमिगत जल से सिंचाई को मिली मजबूती, बदली किसान परिवार की आर्थिक तस्वीर

विदिशा (निप्र)। खेती में सिंचाई की समुचित व्यवस्था किसी भी किसान की सफलता की आधारशिला होती है। विशेष रूप से रबी सीजन में पानी की कमी किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। ऐसे में मध्यप्रदेश शासन की राज्य पोषित नलकूप खनन योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना का लाभ लेकर विदिशा जिले के विकासखंड नटेरन की कृषक श्रीमती तुरसाबाई करणसिंह कोरी ने न केवल सिंचाई की समस्या का स्थायी समाधान किया, बल्कि अपनी खेती को लाभकारी बनाते हुए परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत की है। श्रीमती तुरसाबाई बताती हैं कि पहले उनके खेत में सिंचाई का कोई स्थायी साधन उपलब्ध नहीं था। वर्षा पर निर्भर खेती होने के कारण हर सीजन में पानी की कमी का सामना करना पड़ता था। समय पर सिंचाई नहीं होने से फसल उत्पादन प्रभावित होता था और कई बार फसल खराब होने से आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता था। सीमित संसाधनों के कारण खेती से अपेक्षित आय नहीं मिल पा रही थी। इसी दौरान कृषि विभाग के क्षेत्रीय कृषि अधिकारी श्री राघवेंद्र अहिरवार के नियमित प्रक्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्हें राज्य पोषित नलकूप खनन योजना की जानकारी मिली। योजना की उपयोगिता समझने के बाद उन्होंने आवेदन किया, जिसे स्वीकृति मिलने पर शासन से नलकूप खनन के लिए 40 हजार रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ। इस आर्थिक सहायता से उन्होंने अपने खेत में नलकूप का निर्माण कराया और सिंचाई की स्थायी व्यवस्था स्थापित कर ली। नलकूप बनने के बाद उनके खेत में पूरे वर्ष आवश्यकतानुसार सिंचाई संभव हो सकी। इसका सीधा लाभ फसल उत्पादन पर दिखाई दिया। पहले की तुलना में उत्पादन में 20 से 25 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई। वहीं सिंचाई पर होने वाला अतिरिक्त खर्च भी काफी कम हो गया, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 30 हजार रुपये की अतिरिक्त बचत होने लगी। उत्पादन बढ़ने और लागत घटने से परिवार की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। श्रीमती तुरसाबाई के पति श्री करण सिंह कोरी का कहना है कि अब फसल को समय पर पर्याप्त पानी मिल जाता है, जिससे उसकी गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है और बेहतर उत्पादन प्राप्त हो रहा है। उन्होंने शासन की इस जनहितैषी योजना के लिए आभार व्यक्त करते हुए जिले के अन्य किसानों से भी योजनाओं का लाभ लेकर अपनी खेती को समृद्ध बनाने की अपील की है।

लंबित आवेदनों के त्वरित निराकरण पर कलेक्टर का जोर

- सीएम हेल्पलाइन, जनहित योजनाओं, शिक्षा, कृषि एवं अन्य विभागों की प्रगति का लिया जायजा
- शत-प्रतिशत प्रवेश और विद्यार्थियों को सभी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित आवेदनों, जनकल्याणकारी योजनाओं तथा शासन द्वारा संचालित अभियानों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से सीएम हेल्पलाइन, सीएम मॉनिटर, सांसद, प्रभारी मंत्री एवं अन्य वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त लंबित आवेदनों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर जोर देते हुए विभागीय अधिकारियों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में

स्कूलों में फर्नीचर व मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा

विभागवार लंबित प्रकरणों की जानकारी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई। कलेक्टर ने कहा कि आमजन की शिकायतों का समयबद्ध और संतोषजनक निराकरण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी विभागों को जनहित से जुड़े मामलों में गंभीरता और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनहितैषी योजनाओं एवं अभियानों की अद्यतन प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री गुप्ता ने निर्देश दिए कि जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में शत-प्रतिशत विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित किया जाए तथा उनकी नियमित उपस्थिति दर्ज हो। उन्होंने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें, साइकिल, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, समग्र आईडी सहित शासन द्वारा प्रदाय सभी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं।

उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि जिले के सभी शासकीय विद्यालयों में निर्बाध बिजली आपूर्ति रहे तथा प्रत्येक कक्षा में पंखों की व्यवस्था हो, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। बैठक में जिला शिक्षा केंद्र द्वारा जिले के विद्यालयों में फर्नीचर की उपलब्धता संबंधी समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट के अनुसार जिले के 1,829 विद्यालयों की 5,523 कक्षाओं का परीक्षण किया गया, जिनमें से 3,800 कक्षाओं में विद्यार्थियों के बैठने के लिए पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध है, जबकि 1,723 कक्षाओं में अभी भी फर्नीचर की कमी बनी हुई है। वहीं 172 विद्यालयों से सत्यापित फीडबैक प्राप्त नहीं हुआ है। आंकड़ों के अनुसार विदिशा विकासखंड में सर्वाधिक 913 कक्षाओं में पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध है।

इसके बाद सिरोंज में 691, बासौदा में 545, नटेरन में 521 तथा कुरवाई में 508 कक्षाओं में पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध होने की जानकारी दी गई। दूसरी ओर लटेरी विकासखंड की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक पाई गई, जहां 581 में से 369 कक्षाओं में फर्नीचर का अभाव है। सिरोंज में 541, विदिशा में 293, बासौदा में 271, नटेरन में 141 तथा कुरवाई में 108 कक्षाओं में भी फर्नीचर की कमी दर्ज की गई। ग्यारसपुर विकासखंड जिले का एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा, जहां सभी 410 कक्षाओं में पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध होने की जानकारी प्रस्तुत की गई।

वनमहोत्सव 2026 के तहत नर्मदा तट पर 600 पौधों का हुआ रोपण

नर्मदापुरम (निप्र)। वनमहोत्सव 2026 के अंतर्गत नर्मदापुरम में नर्मदा नदी के तट पर हर्बल पार्क से चौरे घाट तक वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरण में वृद्धि तथा नर्मदा तट के पारिस्थितिक संतुलन को सुदृढ़ करना रहा।

कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। इस अवसर पर लोकसभा सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी, राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया, कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री साई कृष्ण एस. थोटा एवं वनमंडलाधिकारी श्री गौरव शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

वनमहोत्सव के दौरान कुल 600 पौधे रोपे गए। इनमें वट, पीपल, अर्जुन, चिरोल, नीम, आंवला सहित विभिन्न फलदार एवं छायादार प्रजातियों के पौधे शामिल रहे। इन पौधों के माध्यम से नर्मदा तट को अधिक हरित एवं पर्यावरणीय दृष्टि से समृद्ध बनाने का प्रयास किया गया।

स्कूल-कॉलेजों में चलाएं नशा विरोधी जागरूकता अभियान

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कार्यालय के रेवा सभा कक्ष में नारकोटिक्स एवं अन्य नशीली दवाओं की रोकथाम तथा बेहतर समन्वय के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री मिश्रा ने पूर्व बैठक की कार्रवाई विवरण की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई एवं व्यापक जनजागरूकता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री मिश्रा ने निर्देशित किया कि जिले के सभी स्कूलों एवं महाविद्यालयों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, उनके दुष्प्रभावों तथा नशामुक्ति के संबंध में विशेष जागरूकता अभियान संचालित किए जाएं। उन्होंने जिले में संचालित नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों का नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करने के निर्देश दिए।

किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान पर कलेक्टर का जोर

संतुलित उर्वरक उपयोग और सिंचाई व्यवस्था की हुई समीक्षा

विदिशा (निप्र)। किसानों को खाद, बिजली, सिंचाई, फसल बीमा तथा समर्थन मूल्य पर उपज विक्रय से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित बेतवा सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ ऊर्जा, कृषि, जल संसाधन तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में किसानों द्वारा खाद की उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति, सिंचाई सुविधाओं, फसल बीमा दावों के निराकरण तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज खरीदी से संबंधित समस्याओं और सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए

कि किसानों की शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए, जिससे उन्हें खेती-किसानी के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कलेक्टर श्री गुप्ता ने किसानों से अपील की है कि वे मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर ही संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक पद्धति से उर्वरक प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, उत्पादन लागत कम होती है तथा फसल की गुणवत्ता और उत्पादकता में वृद्धि होती है। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड और मिट्टी परीक्षण के परिणामों के अनुरूप उर्वरक उपयोग के प्रति जागरूक किया जाए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जिले में खाद वितरण , सिंचाई व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति और समर्थन मूल्य पर उपज खरीदी की तैयारियों की लगातार निगरानी की जा रही है। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर किसानों को समय पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए , ताकि खरीफ सीजन के दौरान किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। डीएपी खाद आपूर्ति के संबंध में भी विचार विमर्श किया गया है। किसान संघ के प्रतिनिधि को बताया गया कि प्रदेश में सबसे ज्यादा डीएपी पूर्ति विदिशा जिले में अब तक की गई है। बैठक में डीएपी के वैकल्पिक व्यवस्था, नैनो डीएपी का उपयोग करने की सलाह दी गई है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने किसानों से अहवान किया है कि कृषि क्षेत्रों में हो रहे नवाचारों का अधिकार से अधिक जिले के कृषक बंधु उपयोग कर जिले की ख्याति में वृद्धि करें ताकि अन्य किसानों को प्रेरणा मिल सकें।

किसने इन बिंदुओं से कराया अवगत

बैठक में भारतीय किसान संघ द्वारा अपनी समस्याओं से संबंधित विभिन्न बिंदुओं से अवगत कराया जिनमें सीमांकन, गलत सीमांकन के चलते हो रही परेशानियां, पटवारी नक्शा एवं सैटेलाइट नक्शा का सही मिलान जब तक ना हो रोवर, ईटीएसएम मशीन से सीमांकन करने पर शीघ्र रोक लगाकर जरीब से सीमांकन करने। बीमा खरीफ 2025 में अति वृष्टि के कारण बर्बाद फसल का मुआवजा दिलाने, राजस्व विभाग में रजिस्ट्री के बाद समय सीमा में नामांतरण करने, मूंग ग्रीष्मकालीन मूंग की शत-प्रतिशत खरीदी करने, जिले की सभी मंडियों में मंडी बोर्ड के आदेश 26 जून 2020 का पालन करते हुए बीओटी (धर्म कांटे) से तुलाई कराने, आकाशीय बिजली से ग्राम करैया तहसील शमशाबाद निवासी लाखन सिंह बंजारा की मृत्यु 23 जून 2026 को हुई थी मृतक के परिवार को शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने सहित अन्य समस्याएं शामिल रहीं।

सीएम डा मोहन यादव की बड़ी सौगात

पीथमपुर में 272 करोड़ की नई यूनिट, हजारों रोजगार और निवेश को मिलेगी रफ्तार

सीएम धार पीथमपुर में प्लांट को हरी झंडी दिखाकर शुरू कराते हुए

धार (नप्र)। एमपी के औद्योगिक विकास को नई गति देने की दिशा में बुधवार को एक बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 272 करोड़ रुपये की नई विनिर्माण इकाई का भूमि-पूजन किया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पीथमपुर प्रदेश के औद्योगिक विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है और यह नई इकाई निवेश, उत्पादन तथा रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी।

सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिली है। उन्होंने बताया कि पीथमपुर में स्थापित होने वाली यह यूनिट मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने लियुगोंग समूह को बधाई देते हुए कहा कि इस परियोजना से प्रदेश में विकास का नया अध्याय लिखा जाएगा।

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश का माहौल लगातार बेहतर हो रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद प्रदेश को 30 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि केवल 1 जनवरी से 30 जून तक 76,862 करोड़ रुपये से अधिक के नए निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे करीब 82 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।

लियुगोंग कंपनी अभी तक पीथमपुर प्लांट में सालाना 3,250 मशीनें बनाती थी। इस नए 272 करोड़ के निवेश और आधुनिक प्लांट के तैयार होने के बाद इसकी उत्पादन क्षमता बढ़कर सीधे 7,500 मशीनें प्रति वर्ष हो जाएगी। रिसर्च और आधुनिक निर्माण का हब- यह यूनिट देश में कंस्ट्रक्शन और अर्थ-मूविंग मशीनरी के लिए रिसर्च और निर्माण का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगी।

नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के संचालन से स्थानीय युवाओं के लिए बड़ी संख्या में तकनीकी और गैर-तकनीकी रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

हमारी सरकार केवल घोषणा नहीं करती

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने का काम भी करती है। उन्होंने हाल के दिनों में प्रदेश में शुरू हुई प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि शिवपुरी में अडाणी डिफेंस यूनिट, उज्जैन में पेप्सिको की विनिर्माण इकाई, सतगढ़ी में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क और नीमच में नई औद्योगिक इकाइयों की शुरुआत इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। कांग्रेस ने अपने लंबे शासनकाल में वो औद्योगिक विकास नहीं किया, जो हमारी सरकार ने पिछले 6 महीने में करके दिखा दिया है। पूरी दुनिया का भरोसा अब मध्य प्रदेश पर बढ़ रहा है

लियुगोंग इंडिया की उत्पादन क्षमता दोगुनी से अधिक

उन्होंने बताया कि वर्तमान में लियुगोंग इंडिया की उत्पादन क्षमता लगभग 3,250 मशीन प्रतिवर्ष है, जो नई यूनिट शुरू होने के बाद बढ़कर 7,500 मशीन प्रतिवर्ष हो जाएगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन को नई मजबूती मिलेगी।

नया संयंत्र स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर देगा- कार्यक्रम में लियुगोंग इंडिया के ग्लोबल वाइस चेयरमैन ल्यू गोवेन ने कहा कि नया संयंत्र स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा और अनुसंधान एवं मशीन निर्माण का प्रमुख केंद्र बनेगा। वहीं कंपनी के प्रतिनिधि वरुण विजयवर्गीय ने कहा कि वर्ष 2009 से मध्यप्रदेश में उत्पादन कर रही कंपनी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आधुनिक निर्माण उपकरण तैयार कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में औद्योगिक विकास और तेज गति से आगे बढ़ेगा।

आरजीपीवी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

भोपाल(नप्र)। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जून-जुलाई 2026 की परीक्षाओं के संचालन को देखते हुए परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी प्रो. अर्चना तिवारी से वापस लेकर प्रो. संजीव शर्मा को सौंप दी है।

इसके साथ ही प्रो. अर्चना तिवारी को परीक्षा संबंधी सभी कार्यों से तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया गया है। आदेश में उनके कार्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों को भी परीक्षा कार्यों से अलग करने की बात कही गई है।

बायोटेक्नोलॉजी स्कूल के निदेशक पद से भी हटाया गया- विश्वविद्यालय के उपकुलसचिव (प्रशासन) द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रो. अर्चना तिवारी को स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के प्रभारी निदेशक पद से भी मुक्त कर दिया गया है। उनके स्थान पर डॉ. जितेन्द्र अग्रवाल को आगामी आदेश तक प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया है।इतना ही नहीं, प्रो. तिवारी को डायरेक्टर, आईक्यूएसी सहित सभी अतिरिक्त दायित्वों से भी मुक्त कर दिया गया है।

300 फीट ऊंचे टॉवर पर 3 दिन से आमरण अनशन

भारी बारिश में रेस्क्यू टीमें फेल, बात करने पहुंचे अफसरों पर रॉड से हमला

छिंदवाड़ा (नप्र)। शहर के तीन शेर चौक स्थित बीएसएनएल के करीब 300 फीट ऊंचे टावर पर चढ़े युवक का हाईवोल्टेज ड्रामा लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। सोमवार शाम टावर पर चढ़ा युवक बुधवार तक 45 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नीचे नहीं उतरा। जिला प्रशासन, पुलिस, नगर पालिका और छिंदवाड़ा से बुलाई गई विशेष रेस्क्यू टीम ने घंटों तक अभियान चलाकर युवक को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन वह किसी भी समझाइश के आगे झुकने को तैयार नहीं हुआ। इसके चलते प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती युवक की जान बचाते हुए उसे सुरक्षित नीचे उतारने की बनी हुई है।

घटना ने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तीन शेर चौक पर सुबह से देर शाम तक लोगों की भीड़ जुटी रही। हर किसी की निगाहें टावर की चोटी पर बैठकर नीचे देख रहे युवक पर टिकी रहीं। कई लोग दुआ करते नजर आए कि वह सुरक्षित नीचे उतर आए, जबकि प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है।

टावर की चोटी पर बैठा है युवक, हाथ में लोहे की रॉड- जानकारी के अनुसार युवक टावर के सबसे ऊपरी प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ है। उसके हाथ में लोहे की एक रॉड होने के कारण रेस्क्यू टीम बेहद सतर्कता के साथ अभियान चला रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस स्थिति में किसी भी तरह की जल्दबाजी गंभीर परिणाम ला सकती है। इसलिए पूरी कार्रवाई मनोवैज्ञानिक तरीके से बातचीत और विश्वास कायम करने पर केंद्रित है।

भोपाल के टाइगर मूवमेंट एरिया में पहाड़ी की कटाई

जेसीबी-पोकलेन चलते देख लोग विरोध में उतरे, पुलिस से शिकायत

भोपाल (नप्र)। भोपाल के टाइगर मूवमेंट एरिया स्थित पहाड़ी पर पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है। इसके चलते लोग विरोध में उतर आए। उन्होंने मामले में पुलिस से भी शिकायत की है।

मामला सुबह 11 बजे सामने आया। जेसीबी और पोकलेन की मदद से पहाड़ी को समतल किया जा रहा था। जिसकी जद में कई पेड़ भी आ गए और वे उखड़ गए। यह जमीन अकबरपुर गांव के सर्वे नंबर-

तीन पर है, जो कि सरकारी भूमि है। बाघ एक्सपर्ट राशिद नूर ने बताया कि यहां अवैध रूप से पेड़ों की कटाई करके अवैध उत्खनन एवं ढलान की समतल करने की प्रकिया चल रही है एवं अवैध प्लाटिंग की जा रही है। इसकी पहले भी एनजीटी में शिकायत की जा चुकी है। एनजीटी के आदेश में स्पष्ट लिखा है कि सरकारी भूमि का कलेक्टर के माध्यम से एवं रेवेन्यू रेंडर्स के आधार पर पूर्ण सीमांकन किया जाए एवं कॉलोनी की जो जमीन उसका भी सीमांकन करके उसकी भी सीमा निर्धारित किया जाए।

खसरों से छेड़छाड़ का आरोप- पर्यावरणविद् नूर ने बताया, रसूखदारों ने खसरों से छेड़छाड़ की है। जिला प्रशासन से मांग की गई है कि पटवारी और राजस्व निरीक्षक के माध्यम से जांच कराई जाए। दानिश सेक्टर-3 और 5 में अवैध कब्जे के प्रकरण तहसील न्यायालय में चल रहा है। मास्टर प्लान के हिसाब से आठ डिग्री से ज्यादा ढाल पर निर्माण की अनुमति नहीं है। बावजूद प्लाटिंग की गई है।

ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत

भोपाल (नप्र)। भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पार करते समय एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवक ट्रैक पार करते समय मोबाइल की स्क्रीन देख रहा था। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

दोस्त से मिलने निकला था- पुलिस के मुताबिक, 32 वर्षीय मनीष प्रजापति, जहांगीराबाद के नीमवाली सड़क इलाके का रहने वाला था। वह एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। मंगलवार रात करीब 11:30 बजे खाना खाने के बाद वह टहलने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान वह पैदल ऐशबाग में रहने वाले अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा था।

बरखेड़ी के पास हुआ हादसा- बरखेड़ी के पास रेलवे लाइन पार करते समय मनीष ट्रेन की चपेट में आ गया। टक्कर इतनी तेज थी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर ऐशबाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

खरगोन में उफनाती रूपारेल नदी में बहा युवक, मौत

भोपाल (नप्र)। सेंधवा में ग्रामीण अंचलों के नदी-नाले उफान पर हैं। शाजापुर में टीचर जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे हैं। बैतूल में भी बच्चे नाला पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। पन्ना के बृहस्पति कुंड और पांडव फॉल भी काफी सुंदर दिख रहे थे। मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। 24 घंटे में 40 से ज्यादा जिलों में बारिश होने से कई जगह जनजीवन प्रभावित हुआ है। उफनती नदियां और नाले हादसों की वजह बन रहे हैं। खरगोन में रूपारेल नदी के तेज बहाव में एक युवक बह गया, जबकि रतलाम में अंडरब्रिज में पानी भर गया, वहीं शाजापुर में शिक्षकों को उफनता नाला पार कर स्कूल पहुंचना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले एक-दो दिनों तक कई जिलों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। 24 घंटों में सबसे ज्यादा 2.4 इंच बारिश धार में दर्ज की गई, जबकि राजगढ़, रतलाम, शिवपुरी, टीकमगढ़, खरगोन, भोपाल और उज्जैन समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हुई।

पति के साथ रिश्वत ले रही थी महिला सरपंच

20,000 रुपए हाथ में लेते ही ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने दबोचा

शिवपुरी (नप्र)। ग्वालियर लोकायुक्त ने शिवपुरी में बड़ी कार्रवाई की है। महिला सरपंच और उसके पति को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। दोनों कूप निर्माण के बिल को पास करने के लिए फरियादी से रिश्वत की मांग कर रहे थे। इसके बाद पीड़ित ने लोकायुक्त से शिकायत की थी।

रिश्वत मांगने की शिकायत की- शिवपुरी जिले के पीछोर तहसील स्थित जुंगीपुर गांव के राहुल ने लोकायुक्त से शिकायत की थी। शिकायत में फरियादी ने कहा कि जुंगीपुर गांव में पिता के खेत में कपिलधारा योजना के तहत स्वीकृति कूप का निर्माण करवाया। कूप निर्माण में सामग्री के भुगतान बिल पर हस्ताक्षर के लिए महिला सरपंच और उसके पति ने रिश्वत की मांग की।

लोकायुक्त ने किया सत्यापन- शिकायत जुंगीपुर गांव के महिला सरपंच केशवती कोली के खिलाफ थी। सरपंच और उसके पति ने 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त ने मामले का सत्यापन किया। जांच के दौरान मामला सही पाया गया। इसके बाद ट्रैप दल का गठन किया है।

रिश्वत लेते पकड़ा गया

ग्वालियर लोकायुक्त ने आठ जुलाई को सरपंच केशवती कोली और उसके पति खेमचंद कोली को 20000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। इसके बाद दोनों के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन अधिनियम 2018 और धारा 61(2) बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर लोकायुक्त टीम द्वारा कार्यवाही की जा रही है।गौरतलब है कि ट्रैप दल का गठन लोकायुक्त निरीक्षक उपेंद्र दुबे के नेतृत्व में की गई थी। मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। साथ पंचायत में हड़कंप मच गया है।

हजारों करोड़ की 'सिंधिया विरासत' और तीन पीढ़ियों की 'कानूनी जंग' पर समझौते के संकेत

ग्वालियर/नई दिल्ली । तीन पीढ़ियों और करीब चार दशक से चल रहा परिवार का संपत्ति का अनसुलझा विवाद अब सुलझने की कगार पर है। चौंकिए मत... राजघरानों में संपत्ति की जंग ऐसे ही दशकों चलती रहती है। यह मामला भी सिंधिया राजघराने से जुड़ा है। जिसमें सिंधियाओं की हजारों करोड़ रुपयों की संपत्ति का कानूनी विवाद अब समझौते की दहलीज पर पहुंचता दिख रहा है। देश की निचली से लेकर उपरी अदालतों में इस विवाद को सुलझाने की कोशिशें हुईं तो, लेकिन फलीभूत नहीं हुईं। आज भी विभिन्न अदालतों में लंबित मुकदमों की एक लंबी लिस्ट है। फिर क्या ऐसा हुआ कि 40 सालों से चल रहा यह विवाद, अपने अंतिम चरण में है...।

1980 के दशक से शुरू हुई सिंधिया राजघराने की विरासत की जंग- सिंधिया परिवार में संपत्ति विवाद की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। जब तत्कालीन राजमाता विजयाराजे सिंधिया और उनके पुत्र माधवराव

सिंधिया के बीच संपत्ति को लेकर मतभेद सामने आए। बाद में यह विवाद अगली पीढ़ी तक पहुंच गया। माधवराव सिंधिया के निधन के बाद उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्तराधिकार का दावा किया। दूसरी ओर उनकी बुआओं वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे, उषा राजे तथा स्वर्गीय पद्मावती राजे के उत्तराधिकारियों ने भी संपत्ति में अपने अपने अधिकारों का दावा किया।

देखा जाए तो यह विवाद केवल सिंधियाओं के महल, ग्वालियर का जय विलास पैलेस की संपत्ति और महज गहनों के स्वामित्व तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें ट्रस्टों का नियंत्रण और वसीयत जैसे कई कानूनी मुद्दे शामिल थे, जिसने पीढ़ियों तक अदालतों का सफर तय किया। इस मामले में विवादित संपत्तियां ग्वालियर, मुंबई सहित कई स्थानों पर फैली हुई हैं। इन संपत्तियों का अनुमानित मूल्य हजारों करोड़ रुपये बताया जाता रहा है।

पुराने भोपाल में रातभर चला सघन चेकिंग अभियान

संदिग्धों से पूछताछ, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई

भोपाल (नप्र)। भोपाल के पुराने शहर में मंगलवार देर रात पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर लगाम लगाने के लिए सघन चेकिंग और सर्च अभियान चलाया। इस दौरान कई थाना क्षेत्रों में प्रमुख चौराहों, बाजारों और संवेदनशील इलाकों में बैरिकेड्स लगाकर वाहनों की जांच की गई।

संदिग्ध लोगों से पूछताछ- पुलिस ने देर रात बिना उचित कारण घूम रहे लोगों से पूछताछ की और उनकी पहचान की जांच की। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए आवश्यक कार्रवाई भी की गई। अभियान के दौरान दोपहिया और चारपहिया वाहनों के दस्तावेज जांचे गए। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई।

संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त- पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गश्त भी की। लोगों से अपील की गई कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।

आगे भी जारी रहेगा अभियान- डीसीपी

आयुष गुप्ता ने बताया कि अपराधियों में कानून का डर बनाए रखने और शहर में शांति बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण के साथ-साथ ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए भी नियमित कार्रवाई जारी रहेगी।

अब बगलामुखी में दान चोरी, निजी खातों में जमा हुआ चढ़ावा

शिकायत के बाद कलेक्टर ने 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई, 7 दिन में मांगी रिपोर्ट

आगर मालवा (नप्र)। अयोध्या के राम मंदिर के बाद अब मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर से चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर 7 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है।

गैर-सरकारी समिति पर लगे आरोप- जानकारी के अनुसार, कलेक्टर कार्यालय में की गई शिकायत में कहा गया है कि मंदिर परिसर में शासकीय प्रबंधन समिति से अलग एक गैर सरकारी समिति श्रद्धालुओं से नकद, सोना और चांदी के रूप में दान इकट्ठा कर रही थी। आरोप है कि चढ़ावे की राशि के लिए निजी बैंक खातों का उपयोग किया गया और वित्तीय रिकॉर्ड में गड़बड़ियां की गईं।

जिला पंचायत सीईओ की अगुआई में जांच- जांच दल की अगुआई जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बी.एस. सोलंकी करेंगे। समिति में जिला कोषालय अधिकारी मनीष सोलंकी और नलखेड़ा नगर परिषद की मुख्य नगरपालिका अधिकारी मिनी अग्रवाल को सदस्य बनाया गया है।

इन तीन बिंदुओं की होगी पड़ताल

क्या किसी अपंजीकृत या गैर-सरकारी समिति द्वारा समानांतर रूप से दान लिया जा रहा था?

रसीद पुस्तिकाओं, बैंक खातों और अन्य दस्तावेजों के आधार पर नकद, स्वर्ण और चांदी का सही लेखा-जोखा क्या है?

क्या किसी शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, मंदिर प्रबंधन या अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है?

निरीक्षण के दौरान मिली थीं शिकायतें

जानकारी के मुताबिक, हाल ही में कलेक्टर प्रीति यादव ने मंदिर का निरीक्षण किया था। इसी दौरान कुछ लोगों ने मौखिक रूप से दान और वित्तीय लेन-देन में अनियमितताओं की शिकायत की थी, जिसके बाद जांच के आदेश जारी किए गए।

गर्भगृह के सौंदर्यीकरण की भी जांच- सूत्रों के अनुसार, मंदिर के गर्भगृह में सोने और चांदी से कराया गया सौंदर्यीकरण भी इसी समिति के माध्यम से हुआ था। श्रद्धालुओं से मिले सोना, चांदी और नकद दान के संग्रह और उपयोग से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच की जा सकती है।

इस मामले में कलेक्टर प्रीति यादव का पक्ष जानने के लिए संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। जांच दल के सदस्य मनीष सोलंकी ने बताया कि उन्हें समिति में शामिल किए जाने की जानकारी मिल चुकी है।

तंत्र साधना, मिर्च अनुष्ठान के लिए पहुंचते हैं श्रद्धालु

नलखेड़ा में लखुंदर नदी किनारे स्थित मां बगलामुखी मंदिर देश के प्रमुख शक्तिपीठों में माना जाता है। मान्यता है कि यहां मां जाग्रत स्वरूप में विराजमान हैं और तंत्र साधकों के लिए यह सबसे अहम साधना स्थलों में से एक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यहां होने वाले तांत्रिक और मिर्च अनुष्ठान से कोर्ट केस में विजय, शत्रुओं पर जीत और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। यह भी माना जाता है कि महाभारत काल में पांडवों को इसी स्थान पर विजय का वरदान प्राप्त हुआ था।

मंदिर में माता तीन स्वरूपों में विराजती हैं। दाईं ओर महालक्ष्मी, बाईं ओर सरस्वती और मध्य में मां बगलामुखी के दर्शन होते हैं। मंदिर का गर्भगृह 3 करोड़ रुपए से अधिक के स्वर्ण, करीब 65 लाख रुपए की चांदी और बहुमूल्य आभूषणों से सुसज्जित है। मंदिर के सामने 80 फीट ऊंची दीपमाला भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है।